पेज 03 में...
सदन में म्याऊं म्याऊं की गूंज

साप्ताहिक
शहर सत्ता
PRGI NO. CTHIN/25/A2378
सोमवार, 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025
हम दिखाएंगे आईना...

पेज 08 में...
जनता की आस्था सबसे बड़ी शक्ति

वर्ष : 01 अंक : 41 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com

पेज 12 लाल आतंक को फुटबॉल किक

'रमन' सूबाई सियासत के 'डॉक्टर'

पीएम मोदी के कर्तव्य बोध के आवाहन से प्रेरित सत्र

- सदस्यों ने कुल 628 सवाल लगाए हैं
- 333 तारांकित और 295 अतारांकित प्रश्न
- शीत सत्र को लेकर कुल 48 ध्यानाकर्षण
- 139 लोक महत्व के विषय पर चर्चा होगी

मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी (मो.7000681023)

नया भवन, नई व्यवस्था के साथ पहली बार रविवार से विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। सूबाई सियासत के सुपर स्टार डॉ रमन सिंह का छत्तीसगढ़ की जनता ने शानदार 15 वर्ष का मुख्यमंत्री कार्यकाल भी देखा और अब संसदीय कार्य में पेश किए नज़ीर से भी सभी वाकिफ हो गए। नया भवन, नई व्यवस्था के साथ पहली बार रविवार से विधानसभा सत्र की अनूठी शुरुआत ने उन्हें अलहदा मुकाम में ला खड़ा किया है। पार्षद, सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री फिर विधायक के बाद विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी तक का उनका सफर उन्हें संसदीय कार्यों का काबिल और बेदाग सियासी शख्सियत बनाता है। शीतकालीन सत्र से पूर्व नए विधानसभा भवन की कुर्सी पर बैठकर डॉ. रमन ने जांचा, आसंदी पर भी बैठे, पहली दफा रविवार से सत्र की शुरुआत करने वाले वे एकमात्र विधानसभा अध्यक्ष भी कहलायेंगे।

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर खास से शुरू हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, जब रविवार अवकाश के दिन भी विधानसभा की कार्यवाही होगी। सामान्य तौर पर सदन का अवकाश होता है, परंतु खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्तव्य बोध के आवाहन से प्रेरित होकर रविवार को सदन की कार्रवाई सुनिश्चित की गई, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद विधानसभा की पहली बैठक 14 दिसंबर को हुई थी।

25 वर्षों की यात्रा आज भव्य नए विधानसभा भवन तक आ पहुंची है। गुरुवार को डा. रमन ने सदन की कुर्सियों का भी अवलोकन किया। आसंदी पर बैठकर देखा, साथ ही मंत्री, विधायकों की कुर्सियों का भी बैठकर परीक्षण किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा, हम पेपरलेस और बायोमैट्रिक जैसी आधुनिक सुविधाओं की ओर बढ़ रहे हैं। 14 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की विधानसभा के 25 साल पूरे हो रहे हैं। ये रजत जयंती वर्ष उपलब्धि से भरपूर रहा। उन्होंने कहा, हम पेपरलेस और बायोमैट्रिक जैसी आधुनिक सुविधाओं की ओर बढ़ रहे हैं। 14 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की विधानसभा के 25 साल हो रहे हैं। बीते 25 वर्षों में कुल 76 सत्रों में 773 बैठकें हुई हैं और सदन की कार्यवाही 3456 घंटे 19 मिनट चली है।

14 दिसंबर 2000 की याद में 14 दिसंबर 2025

14 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की विधानसभा के 25 साल हो रहे हैं। बीते 25 वर्षों में कुल 76 सत्रों में 773 बैठकें हुई हैं और सदन की कार्यवाही 3456 घंटे 19 मिनट चली है। प्रथम विधानसभा की बैठक 14 दिसंबर 2000 को राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में आयोजित की गई थी, इसलिए रविवार होने के बाद भी 14 दिसंबर 2025 को सत्र आहूत किया गया है, ताकि इस दिन को यादगार बनाया जा सके।

क्या है विजन 2047

छत्तीसगढ़ विजन 2047 के माध्यम से राज्य के 13 प्रमुख क्षेत्रों में 10 मिशनों के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को संतुलित रूप से आगे बढ़ाया का प्लान तैयार किया गया है। इनमें कृषि मैन्युफैक्चरिंग, पर्यटन, संस्कृति, लॉजिस्टिक्स और आईटी से लेकर जैविक खेती और शिक्षा तक का समावेश है। विजन 2047 के माध्यम से राज्य की जीडीपी को 5 लाख करोड़ रुपए से वर्ष 2030 तक 11 लाख करोड़ और वर्ष 2047 तक 75 लाख करोड़ रुपए तक करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।

17 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा का सप्तम सत्र

छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा का सप्तम सत्र 14 दिसंबर से शुरू होगा और 17 दिसंबर तक चलेगा। चार बैठकों वाले इस सत्र के पहले दिन की शुरुआत 14 दिसंबर को राज्य सरकार की दीर्घकालीन विकास रणनीति छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा से होगी। उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जिस पर 16 दिसंबर को चर्चा होगी और उसी दिन इसे पारित भी किया जाएगा।

डॉ. सिंह ने कहा कि चूंकि प्रथम विधानसभा की बैठक 14 दिसंबर 2000 को राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में आयोजित की गई थी, इसलिए रविवार होने के बाद भी 14 दिसंबर 2025 को सत्र आहूत किया गया है, ताकि इस दिन को यादगार बनाया जा सके।

सत्र में आएगा एकमात्र विधेयक

जानकारी के मुताबिक शीत सत्र में एकमात्र छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन (संशोधन) विधेयक 2025 सदन के पटल पर रखा जाएगा। मालूम हो कि शीत सत्र को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने कुल 628 सवाल लगाए हैं, इसमें 333 तारांकित और 295 अतारांकित प्रश्न हैं। इस सत्र में 96.17 प्रतिशत प्रश्न ऑनलाइन लगाए गए हैं। डॉ. सिंह ने यह भी बताया कि शीत सत्र को लेकर कुल 48 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं, 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा की एक सूचना, 9 अशासकीय संकल्प की सूचनाएं, शून्यकाल की 4 और 77 याचिका सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। डॉ. सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों के विधानसभा की यात्रा की विस्तार से जानकारी भी दी।

विपक्ष के लिए विधानसभा ही सबसे अच्छा अवसर : डॉ. रमन

छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि विधानसभा का संचालन सत्तापक्ष और विपक्ष के सहयोग से ही संभव है, लेकिन विपक्ष के सदस्यों के लिए खासकर विधानसभा का सत्र सबसे अच्छा अवसर रहता है, जिसमें वह सरकार से विभिन्न मुद्दों पर सीधे सवाल पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की कल्पना के अनुरूप नई विधानसभा को पेपरलेस और बायोमैट्रिक बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं। पेपरलेस को लेकर चिप्स कार्य कर रहा है।

सदन में मांगेंगे सत्ता पक्ष से जवाब : महंत

नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने कहा कि आमतौर 15, 16 और 17 दिसंबर को जमीन की नई गाइड लाइन दर, धान खरीदी के मुद्दे को लेकर स्थगन लाएंगे। इसके अलावा महासमुंद के एक किसान ने टोकन नहीं मिलने पर दुखी होकर गला काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इन्हीं सब मुद्दों पर विधानसभा में सरकार से जवाब मांगेंगे। डॉ. महंत ने कहा कि विधायक दल की बैठक में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे।

सोमवार को स्थगन संभव

सोमवार को सदन में कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव ला सकती है। जमीन की गाइडलाइन दर और बिजली बिल हॉफ जैसे मुद्दों को लेकर यह प्रस्ताव लाएगी। सत्र के दौरान राज्य सरकार 15 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिस पर 16 को चर्चा कर पारित किए जाने की संभावना है। सत्र के दौरान सदस्यों ने 628 सवाल लगाए है। अब तक राज्य सरकार की ओर से एक विधेयक पेश करने की सूचना दी गई है।

छत्तीसगढ़ विधान सभा के स्थापना दिवस एवं नवीन विधानसभा भवन में सत्र की प्रथम बैठक होने के अवसर पर डॉ रमन सिंह, मान. विधान सभा अध्यक्ष को मान मुख्यमंत्री,मान मंत्री गण एवं मान विधायकों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

त्वरित टिप्पणी

प्रदीप चंद्रवंशी

डाला के सवाल से डोल गया सदन

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन रविवार को कार्रवाई का कांग्रेस ने तो बहिष्कार कर दिया। लेकिन आज विपक्षियों की कमी पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने पूरी कर दी। लग रहा था कि सारे विपक्षी की कमी चंद्राकर जी ही पूरा कर देंगे। संसदीय कार्य के ज्ञाता और पार्टी के विद्वान विधायकों में शुमार अजय चंद्राकर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, उमेश पटेल, देवेंद्र यादव का कॉम्बो पैग लग रहे थे। श्री चंद्राकर ने सदन में चर्चा के दौरान कहा; आज तक 22- 23 बजट की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हुई है।

मामला विधानसभा सत्र के पहले दिन विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा से शुरू हुआ। मंत्री ओपी चौधरी द्वारा विजन ड्यूक्यूमेंट सदन में रखा गया। ओपी चौधरी के प्रस्ताव पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने प्रक्रिया पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा; किस व्यवस्था के तहत चर्चा रही है ? किस प्रावधान के तहत हों रही चर्चा ? तब सभी चौंक गए जब अजय चंद्राकर ने आसंदी से भी पूछा सवाल कि ये शासकीय संकल्प है या अशासकीय संकल्प है ? अजय चंद्राकर ने कहा हमको नहीं पता कि क्या बोलना है... पक्ष में या विपक्ष में ! या विजन को लेकर सलाह देना है।

प्रक्रिया पर सवाल उठते हुए अजय चंद्राकर ने मुख्यमंत्री को विजन डॉक्यूमेंट के लिए बधाई दी। चर्चा में भाग लेते हुए अजय चंद्राकर ने विजन डॉक्यूमेंट चर्चा में कहा- आज तक तय नहीं हो पाया कि रोजगार की परिभाषा क्या है.? कृषि का रकबा कम हो रहा है पर विजन डॉक्यूमेंट में कृषि का योगदान बढ़ने की बात कही गई है ऐसे कैसे संभव है इसकी जांच होना चाहिए। सिंचाई को लेकर हमारे पास कोई पालिसी नहीं है दंतेवाड़ा बस्तर में सिंचाई की क्या व्यवस्था है? मै आलोचना नहीं कर रहा हु,, केवल वस्तु स्थिति बता रहा हूं, कौन से बीज के मामले में हम आत्म निर्भर है? दुग्ध उत्पादन मरणासन्न अवस्था में है, नस्ल सुधार का कोई प्लान नहीं है। डेयरी उत्पादन ने देश में हमारा क्या योगदान है ?

चर्चा के दौरान श्री चंद्राकर ने मंत्री से कहा- आप ने देश दुनिया की तो बात की , भारत में कई उत्पाद को प्रतिबंधित कर दिया पर हमारे पास। कोई योजना नहीं चारा के लिए कुछ नहीं, कृत्रिम गर्भाधान के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आपने औद्योगिक नीति बनाई, उसको लागू करने बनाई या उसमें संशोधन के लिए बनाई। देखता हूं हर महीने एक संशोधन कर देते हो। किन्हीं पर भी छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए नीति नहीं बनी....यहां का लोहा वहां गया बताया गया लेकिन बता दूं कि दुर्घटना वाला तेजस में हमारा लोहा नहीं था। (सब हंस पड़े)

सवाल पर बिफरे मंत्री की आपत्ति

चंद्राकर ने पूछा सवाल; क्या आप लिबरल है ? आप से तो मिलना दूभर है तो बात कैसे हो? मिलना जुलना नहीं होगा तो पुलाव कैसे बनेगा ..? अजय चंद्राकर की टिप्पणी पर श्याम जायसवाल ने आपत्ति जताई। कहा- निजी आरोप ना लगाए। चंद्राकर ने कहा आरोप नहीं लगाया केवल पूछा है। चंद्राकर ने कहा आरोप लगाने की व्यवस्था मुझे पता है। मुझे संसदीय व्यवस्था ना समझाएं। श्याम जायसवाल ने कहा मै भी दो बार का विधायक हूं। चंद्राकर ने फिर कहा; अगर मैने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की हो तो विलोपित करा दीजिए। मंत्री जायसवाल ने आसंदी से मांग की इस टिप्पणी को डिलीट किया जाए। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक के तेवर देखकर कानाफूसी होने लगी कि आज तो सारे विपक्षी की कमी चंद्राकर जी ही पूरा कर देंगे।

सदन में घुसी बिल्ली, म्याऊं-म्याऊं सुनकर हंस पड़े सभी माननीय

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में कार्यवाही के बीच एक बिल्ली घुस आई। इस वक्त वित्त मंत्री ओपी चौधरी विजन डॉक्यूमेंट पर संबोधन दे रहे थे। मंत्री जैसे-जैसे बोल रहे थे, वैसे-वैसे बिल्ली की म्याऊं-म्याऊं तेज हो रही थी। इसे सुनकर मंत्री विधायक करीब 5 मिनट तक ठहाके लगाते रहे। इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री की ओर देखकर मुस्कुरा उठे। स्पीकर, मंत्री, विधायक और अफसर भी कुछ देर तक हंसी नहीं रोक पाए। बाद में कर्मचारियों ने बिल्ली को बाहर निकाला, तब जाकर सदन की कार्यवाही सामान्य रूप से आगे बढ़ सकी।

कांग्रेस की गैरमौजूदगी से लगे आरोप

नए विधानसभा भवन में 'विजन 2047' पर चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस ने पहले दिन सत्र का बहिष्कार किया। इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस डूबती हुई नाव है। इस नाव का डूबना तय है, इसलिए सत्ता पक्ष और भारतीय जनता पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि अंजोर विजन-2047 की सकारात्मक चर्चा में विपक्ष की गैरमौजूदगी को दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्र के पहले ही दिन बहिष्कार कर कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसे छत्तीसगढ़ के भविष्य और विकास को लेकर कोई गंभीर सोच नहीं है।

भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 'विजन 2047' विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में एक ठोस रोडमैप है, जिसे समाज के हर वर्ग से मिले सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि करीब एक लाख लोगों की सलाह इस विजन में शामिल की गई है। चौधरी ने कहा कि भारत युवा आबादी वाला देश है और आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट विजन होना जरूरी है।

उन्होंने कहा आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2047 तक यह 64 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। इससे वर्तमान पीढ़ी को विकास के बड़े अवसर मिलेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इसी सोच के तहत छत्तीसगढ़ के लिए भी विकास का विजन तैयार किया गया है। 'विजन 2047' का उद्देश्य महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को कम करना, शिशु मृत्यु दर में सुधार लाना और कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर को बढ़ाना है।

उद्योग नीति में छत्तीसगढ़ की झलक नहीं- अजय चंद्राकर

वहीं पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि विधानसभा में आज नई प्रक्रिया की शुरुआत हुई। बहस और चर्चा किस मुद्दे पर करनी है? इसका सवाल-जवाब कैसे होगा? तय होना चाहिए। विजन डॉक्यूमेंट के लिए सीएम और वित्त मंत्री को बधाई। उन्होंने पूछा कि 2047 के विजन की नींव क्या है और समग्र परिवर्तन में अब तक क्या गलतियां हुईं, यह सामने आना चाहिए। 'नवा अंजोर' दस्तावेज में केवल शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही फोकस है। चंद्राकर ने कहा कि उद्योग नीति में छत्तीसगढ़ की झलक नहीं है। अजय ने कहा कि उद्योग नीति में मेक इन छत्तीसगढ़ का ध्यान नहीं रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राइस मिल की हालत खराब है। खाद्य मंत्री चाहे तो स्वतंत्र बहस कर सकते हैं।

शहर सत्ता/रायपुर। रविवार 14 दिसंबर से प्रारंभ यह सत्र 17 दिसंबर तक 4 दिन चलेगा। कार्यवाही शुरू होने से पहले कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई। बैठक विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। कांग्रेस विधायकों ने पहले दिन सत्र का बहिष्कार किया है। पहले दिन के सत्र में प्रश्नकाल नहीं हुआ। दूसरे दिन यानी 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक सदन में लॉ एंड ऑर्डर, धान, बिजली, जमीन दर से मुद्दों पर हंगामे के आसार है। शीतकालीन सत्र में विधायकों ने 628 सवाल लगाए हैं। मंत्रियों को इन सवालों के जवाब देने होंगे। इस सत्र में सबसे अहम मुद्दा धर्मांतरण का होगा। जानकारी के अनुसार सरकार धर्मांतरण-संशोधन विधेयक ला सकती है।

सदन में दूसरे दिन हंगामे के आसार

शीतकालीन सत्र में विधायकों ने 628 सवाल लगाए हैं

शहर सत्ता/रायपुर। कांग्रेस विधायकों ने पहले दिन सत्र का बहिष्कार किया है। पहले दिन के सत्र में प्रश्नकाल नहीं हुआ। दूसरे दिन यानी 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक सदन में लॉ एंड ऑर्डर, धान, बिजली, जमीन दर से मुद्दों पर हंगामे के आसार है। शीतकालीन सत्र में विधायकों ने 628 सवाल लगाए हैं। मंत्रियों को इन सवालों के जवाब देने होंगे। इस सत्र में सबसे अहम मुद्दा धर्मांतरण का होगा। नए विधानसभा परिसर में सभागार और अन्य व्यवस्थाएं पूरी हैं। पिछला सत्र पुराने विधानसभा भवन में 18 नवंबर को हुआ था, जिसे अब नए भवन में आगे बढ़ाया गया है। इस बार की व्यवस्था विधायकों और सचिवालय के तय नियमों के अनुरूप की गई है। सत्र के दौरान विधायकों की तैयारियों और तय नियमों के तहत सभी प्रश्न, नोटिस और सूचनाएं समय पर दर्ज होंगी।

सदन में गर्माएगा सड़कों की बदहाल स्थिति का मुद्दा

शीतकालीन सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था, धान खरीदी, सड़कों की स्थिति और राशन वितरण में गड़बड़ी पर चर्चा होगी। इसके चलते नया विधानसभा भवन 3 दिन तक बहस और सियासी हंगामे का केंद्र बनेगा।

6 ध्यानाकर्षण और 3 स्थगन नोटिस स्वीकार होंगे

आज बैठक के पहले दिन विधायकों को सुबह 8 बजे तक नोटिस दाखिल करने का अवसर मिला। इसके तहत ध्यानाकर्षण सूचना, स्थगन सूचना और नियम 267-क के तहत सूचनाएं दी जा सकेंगी। सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि एक सदस्य एक दिन में अधिकतम 2 ध्यानाकर्षण और एक स्थगन नोटिस दे सकता है। पूरे 3 दिन के सत्र में अधिकतम 6 ध्यानाकर्षण और 3 स्थगन नोटिस स्वीकार किए जाएंगे।

साय सरकार लाएगी संशोधित धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम

शहर सत्ता/रायपुर। शीतकालीन सत्र में साय सरकार संशोधित धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम पास कर सकती है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने इसके संकेत दिए हैं। इस अधिनियम के पास होने के बाद प्रदेश में धार्मिक विवाद कम होने की आशंका गृहमंत्री ने जताई है। 22 नवंबर को मीडिया से चर्चा के दौरान गृहमंत्री विजय शर्मा ने दावा किया था कि शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण संशोधन विधेयक आएगा। इस विधेयक के आने के बाद नियमों में कई बदलाव होंगे। धर्मांतरण संशोधन विधेयक निर्माण कमेटी के सदस्यों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर विवाद न बढ़े, इसलिए गृहमंत्री के नेतृत्व में नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट के अनुसार, अब किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना आसान नहीं होगा। धर्म परिवर्तन केवल पूरी प्रक्रिया और नियम कानून का पालन करने के बाद ही किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार धार्मिक स्वतंत्रता कानून भी बनाने जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने या जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर जेल के साथ कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए गृहमंत्री विजय शर्मा ने 52 बैठकों में चर्चा कर मसौदा तैयार करवाया है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

DSP लव ट्रैप विवाद में कारोबारी दीपक टंडन की 'कुंडली' खुली

फोटो फ्रेमिंग से होटल कारोबारी बनने तक, ठगी–वारंट–शिकायतों की लंबी फेहरिस्त

रायपुर/कोरबा। डीएसपी कल्पना वर्मा पर लव ट्रैप और करोड़ों रुपये वसूली के गंभीर आरोप लगाने वाले कारोबारी दीपक उर्फ अंबेडकर टंडन को लेकर अब मामला केवल कथित प्रेमजाल तक सीमित नहीं रह गया है। जैसे-जैसे जांच और पड़ताल आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे टंडन के अतीत से जुड़े ठगी, धोखाधड़ी और विवादों की परतें खुलती जा रही हैं।

छोटे दुकानदार से करोड़पति बनने की कहानी पर सवाल

कोरबा में कभी फोटो फ्रेमिंग की छोटी दुकान चलाने वाला दीपक टंडन कुछ ही वर्षों में रायपुर का बड़ा कारोबारी कैसे बन गया—यह सवाल अब चर्चा के केंद्र में है। रायपुर में उसका अकेला होटल ही पांच करोड़ रुपये से अधिक की लागत का बताया जा रहा है। इसके अलावा कई अचल संपत्तियां, लग्ज़री लाइफस्टाइल और बार-बार विदेश यात्राएं उसकी आर्थिक हैसियत में अचानक आई उछाल की ओर इशारा कर रही हैं।

ठगी के पुराने मामलों का रिकॉर्ड आया सामने

टंडन के खिलाफ पहले से दर्ज धोखाधड़ी के मामलों ने उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्ष 2015 में कोरबा के एसईसीएल दीपका क्षेत्र के कोल कारोबारी से 28 लाख रुपये लेकर कोयला आपूर्ति नहीं करने का मामला सामने आया था। पैसे लौटाने के लिए दिए गए दोनों चेक बाउंस हो गए। वर्ष 2020 में इस मामले में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज हुआ और न्यायालय में पेश नहीं होने पर कटघोरा कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

परीक्षा पर्चा दिलाने के नाम पर भी आरोप

रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नगर निगम की राजस्व निरीक्षक भर्ती

परीक्षा का प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर भी ठगी का मामला दर्ज है। बीरगांव निवासी एक अभ्यर्थी ने शिकायत में आरोप लगाया कि उससे परीक्षा पर्चा दिलाने के नाम पर पैसे मांगे गए।

सक्ती के कारोबारी से 15 लाख की कथित ठगी

सक्ती जिले के कोयला व्यवसायी किशन शर्मा ने भी दीपक टंडन पर 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शर्मा के अनुसार, टंडन ने शासन-प्रशासन में प्रभाव का दावा कर बड़ा कोयला टेंडर दिलाने का झांसा दिया था। रकम लेने के बाद काम नहीं हुआ और दिए गए चेक भी भरोसेमंद नहीं निकले। इस संबंध में पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की है।

इधर, डीएसपी कल्पना वर्मा पर लगाए गए ढाई करोड़ रुपये वसूली के आरोपों ने पूरे प्रकरण को हाई-प्रोफाइल बना दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल

सुलगते सवाल

- अचानक आई संपत्ति का वास्तविक स्रोत क्या है?
- क्या ठगी के पुराने मामलों और वर्तमान आरोपों के बीच कोई सांठगांठ है?
- और क्या लव ट्रैप विवाद की आड़ में कोई और बड़ा आर्थिक खेल सामने आएगा?

किए गए कथित चैट, कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। वहीं डीएसपी वर्मा पहले ही टंडन के बैंक खातों और आय के स्रोतों की जांच की मांग कर चुकी हैं।

निजी जीवन भी विवादों में

दीपक टंडन का निजी जीवन भी विवादों से अछूता नहीं रहा है। पहली पत्नी द्वारा दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें उसे जेल भी जाना पड़ा। दूसरी शादी के बाद भी उसका पारिवारिक जीवन सुर्खियों में रहा है। फिलहाल यह मामला केवल एक अफसर और कारोबारी के बीच विवाद नहीं रह गया है, बल्कि आर्थिक अपराध, संपत्ति जांच और सिस्टम की जवाबदेही से जुड़ा गंभीर विषय बनता जा रहा है।

गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद स्टेंट शिफ्ट होने से उठा सवाल

बिलासपुर। सरकंडा क्षेत्र स्थित मार्क हॉस्पिटल में गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद स्टेंट (बाइल डक्ट में डाली गई ट्यूब) के अपनी जगह से खिसक जाने का मामला सामने आने से चिकित्सा लापरवाही बनाम तकनीकी जटिलता को लेकर बहस शुरू हो गई है। कोरबा निवासी मरीज स्वाति सिंह राजपूत ने इसे सर्जरी के दौरान हुई गंभीर लापरवाही बताया है, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे एक ज्ञात मेडिकल कॉम्प्लिकेशन बताया है।

मरीज ने बरती गई लापरवाही का लगाया आरोप, अस्पताल ने प्रक्रिया को बताया चिकित्सकीय जटिलता

क्या है पूरा मामला

स्वाति सिंह राजपूत को पित्त की थैली में पथरी की समस्या थी। उपचार के लिए वह सरकंडा के मुक्तिधाम मार्ग स्थित मार्क हॉस्पिटल पहुंचीं, जहां सर्जन डॉ. सर्वजीत मरावी द्वारा गॉल ब्लैडर की सर्जरी की गई। ऑपरेशन के दौरान पित्त रस (बाइल) के निकास के लिए स्टेंट लगाया गया, जिसे एक माह बाद निकालने की सलाह दी गई थी।

फॉलो-अप में सामने आई स्थिति

एक माह बाद जब मरीज स्टेंट निकलवाने अस्पताल पहुंचीं, तो किए गए एक्स-रे परीक्षण में पता चला कि स्टेंट अपनी निर्धारित जगह पर नहीं है और वह अंदर की ओर खिसक चुका है। रिपोर्ट सामने आते ही मरीज और परिजनों में चिंता बढ़ गई। मरीज का कहना है कि यह स्थिति सीधे तौर पर सर्जरी के दौरान हुई तकनीकी चूक की ओर इशारा करती है, जो आगे चलकर गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकती है।

'डिजिटल अरेस्ट' का डर दिखाकर रिटायर्ड CRPF कर्मी से 6.30 लाख की ठगी

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर बनाया दबाव

बिलासपुर। साइबर ठगों ने अब डर और कानून के नाम पर ठगी का नया तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। सकरी थाना क्षेत्र के आसमा सिटी निवासी और सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त कर्मचारी को खुद को टेलीकॉम विभाग और मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताने वाले जालसाजों ने 'लॉरेंस बिश्नोई गैंग' से जुड़ा मामला बताकर भयभीत किया और उनसे 6 लाख 30 हजार रुपये की ठगी कर ली।

ऐसे रचा गया साइबर जाल

पीड़ित दिवाकर मंडल (61 वर्ष) के मोबाइल पर 2 नवंबर की सुबह एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को टेलीकॉम विभाग का कर्मचारी बताते हुए कहा कि उनके आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग कर मुंबई में कनाडा के एक बैंक में खाता खोला गया है, जिससे संदिग्ध लेनदेन किया गया है।

फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी ने बढ़ाया डर

इसके बाद कॉल को दूसरे व्यक्ति से जोड़ दिया गया, जिसने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। उसने कहा कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है और पीड़ित का नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े केस में सामने आया है। विश्वास दिलाने के लिए ठगों ने व्हाट्सएप कॉल पर पीड़ित के आधार और पैन कार्ड की कॉपी भी दिखाई, जिससे उन्हें लगा कि मामला सच है।

गिरफ्तारी और वारंट का झांसा

जालसाजों ने पीड़ित को बताया कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है और तुरंत सहयोग नहीं करने पर उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। डर के माहौल में ठगों ने कहा कि यदि उनके खाते में मौजूद रकम एक "सुरक्षित खाते" में ट्रांसफर कर दी जाए, तो पैसों की जांच कर असली अपराधी तक पहुंचा जा सकेगा और पीड़ित का नाम केस से हटा दिया जाएगा।

बालोद में धान घोटाले की आशंका, सरकारी रिकॉर्ड में बड़ा अंतर

बालोद। छत्तीसगढ़ की धान खरीदी और भंडारण व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बालोद जिले के धोबनपुरी और जगतरा धान संग्रहण केंद्रों में वर्ष 2024-25 के दौरान भंडारित और उठाए गए धान के ऑनलाइन रिकॉर्ड और भौतिक स्थिति में बड़ा अंतर सामने आया है। जांच में कुल 43,235 क्विंटल धान कम पाया गया, जिससे राज्य सरकार को करीब 9 करोड़ 97 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है। जिला विपणन कार्यालय द्वारा उपलब्ध डिजिटल डेटा के आधार पर जब स्टोरेज और उठाव का मिलान किया गया, तो यह सामने आया कि कागजों में दर्ज मात्रा के मुकाबले वास्तविक भंडारण कहीं कम है। इस गड़बड़ी को प्रशासन ने गंभीर मानते हुए पुलिस कार्रवाई की है। मामले में जिला विपणन अधिकारी टिकेंद्र राठौर ने धोबनपुरी संग्रहण केंद्र प्रभारी व्यास नारायण ठाकुर, जगतरा संग्रहण केंद्र के प्रभारी क्षेत्र सहायक राणा रंती देव सिंह वर्मा के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 137(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।

CM साय के बयान से छेड़छाड़ का मामला : ₹1 प्रति एकड़ को '₹1 किलो जमीन' बताकर फैलाया भ्रम

सोशल मीडिया 'एडिटिंग' से राजनीति गरमाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के बयान से छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला अब साइबर अपराध और राजनीतिक साजिश के रूप में सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री के कथन को कथित तौर पर एडिट कर जनता के बीच गलत संदेश फैलाने के आरोप में सिविल लाइन थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्या था असली बयान, कैसे बदला गया अर्थ

दो दिसंबर को रायगढ़ के बोईरदादर में आयोजित सामाजिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आदिवासी युवाओं को उद्योग स्थापना के लिए ₹1 प्रति एकड़ की दर से भूमि उपलब्ध कराने की नीति की बात कही थी। आरोप है कि इसी बयान के वीडियो को तकनीकी रूप से एडिट कर उसे '₹1 किलो जमीन देने' जैसा भ्रामक रूप देकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया।

सोशल मीडिया पेज बने जांच के दायरे में

शिकायत के अनुसार, यह एडिटेड वीडियो 'भूपेश है तो भरोसा है' और 'मनीषा गोंड' नामक फेसबुक पेज से शेयर किया गया। भाजपा का आरोप है कि वीडियो को जानबूझकर गलत संदर्भ में प्रस्तुत कर किसानों और आदिवासी समाज को भ्रमित करने का प्रयास किया गया, जिससे शासन की नीतियों को लेकर गलत धारणा बने।

भाजपा ने बताया सुनियोजित साजिश

रायपुर शहर भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि यह मामला सामान्य सोशल मीडिया पोस्ट नहीं बल्कि पूर्व नियोजित राजनीतिक साजिश है, जिसका उद्देश्य मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करना और जनता में अविश्वास पैदा करना है।

संपादकीय

सुकांत राजपूत

विजन-2047 जोखिम और अवसर

दिमाग के घोड़े सही दौड़ाना हों तो मन की लगाम कसें। हमारे 99 प्रतिशत विचार बेकार के होते हैं। और वे केवल हमारी अशांति को व्यवस्थित कर रहे होते हैं। मिटाते नहीं है बढ़ाते हैं, लेकिन व्यवस्थित ढंग से। इन विचारों में अधिकांश समय दूसरे होते हैं। आते-जाते लोगों को निहारना। जो बीत गया, उन यादों को ताजा करना। भविष्य के प्रति भयभीत होते रहना। लेकिन भारत विजन 2047 के केंद्र में विविध विचारधाराओं का संगम है। दिग्गज, नीति निर्माता, विद्वान शिक्षाविद और नवोदित प्रतिभाएं एक साझा मंच पर एकत्रित होंगे।

इंडिया विजन 2047 की खासियत यह है कि यह व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सिर्फ भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समझने पर भी केंद्रित है कि हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। यह भारत के उज्जवल और अधिक नवाचारपूर्ण भविष्य की ओर एक कदम है। इस विज़न से प्रभावित हों और उस वृत्तांत का हिस्सा बनें जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस परिवर्तनकारी अनुभव का हिस्सा बनने का सुनहरा अवसर न चूकें।

भारत को 2047 तक, स्वतंत्रता के 100वें वर्ष, एक विकसित राष्ट्र बनाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, जिसमें आर्थिक समृद्धि, तकनीकी उन्नति, समावेशी विकास और पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है; संपादकीय इसे प्राप्त करने के लिए युवाओं की भूमिका, प्रतिभा के उपयोग, सतत विकास और विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों, जैसे कृषि और शिक्षा, की आवश्यकता पर बल देते हैं, साथ ही चुनौतियों, जैसे मध्यम आय जाल से बचना, पर भी प्रकाश डालते हैं, जिसके लिए 'पंच प्रण' और जनभागीदारी महत्वपूर्ण हैं

आखिर में इतना ही कहना उचित होगा कि हमारा अच्छा-खासा हितकारी मस्तिष्क भी मन के द्वारा फेंके गए विचारों के गुच्छों से आहत हो जाता है। इसलिए दिमाग के घोड़ों को सही दौड़ाना हो तो इसके लिए मन की लगाम को जमकर कसना होगा। क्योंकि विचार एक आजीवन प्रक्रिया है। इसका शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं है। आप अशिक्षित हों या बहुत पढ़े-लिखे हों, यह सिलसिला तो जीवन भर चलेगा। इसलिए इस प्रक्रिया को, जो मृत्यु के साथ ही समाप्त होगी- सदैव प्रशिक्षित करते रहिए, तराशते रहिए और मन के प्रति अत्यधिक सावधान रहिए।

संरक्षा, दायित्व और जन विश्वास नए अधिनियम से क्या हासिल होगा

डा. रतन कुमार सिन्हा

जनता का विश्वास हमेशा से भारत के परमाणु कार्यक्रम की आधारशिला रहा है। देश के सतत, समतापूर्ण और ऊर्जा-सुरक्षित विकास के दृष्टिकोण में यह आधार निहित है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग अत्यधिक संरक्षा, निर्विवाद उत्तरदायित्व और पारदर्शी संचार के साथ किया जाए। संरक्षा, दायित्व और जन विश्वास के स्तंभ केवल अमूर्त आदर्श नहीं हैं; ये भारत के परमाणु उद्योग के व्यावहारिक आधार हैं। जैसे-जैसे हम परमाणु ऊर्जा के लिए एक नए विधायी ढाँचे पर विचार कर रहे हैं, यह पूछना ज़रूरी है कि यह नए अधिनियम से क्या हासिल होगा? मेरे विचार से, इसका उत्तर इन्हीं आधारों को मज़बूत करने में निहित है। इस कानून से अपेक्षा है कि यह जनता के विश्वास से समझौता किए बिना संरक्षा और सशक्तिकरण प्रदान करे, सरलीकरण और सुरक्षा प्रदान करे, नवाचार को प्रोत्साहित करे।

संरक्षा - पूर्णता की संस्कृति को संस्थागत बनाना

परमाणु प्रौद्योगिकी में संरक्षा डिज़ाइन का एक अनिवार्य अंग ही नहीं, बल्कि यह इसका मूल दर्शन होना चाहिए। ट्रॉम्बे में भारत के पहले अनुसंधान रिएक्टरों से लेकर स्वदेशी 700 मेगावाट दाबित भारी पानी रिएक्टरों और अगली पीढ़ी के प्रगत रिएक्टरों तक, डिज़ाइन हमेशा गहन संरक्षा और निश्चेष्ट संरक्षा विशेषताओं द्वारा निर्देशित रही हैं। जब हमने प्रगत भारी पानी रिएक्टर (AHWR) की कल्पना की थी, तो हमारा लक्ष्य न केवल थोरियम के उपयोग को प्रदर्शित करना था, बल्कि यह भी प्रदर्शित करना था कि एक रिएक्टर इसके ऑपरेटर के हस्तक्षेप के बिना भी सुरक्षित रह सकता है – एक ऐसी डिजाइन जो स्वत: सुरक्षित (walk-away safe) हो। वास्तव में, संरक्षा परमाणु ऊर्जा परिनियोजन का एक अभिन्न अंग है।

दायित्व - स्पष्टता के साथ उत्तरदायित्व

नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम (सीएलएनडी अधिनियम) एक अग्रणी कदम रहा है जिसने तीन महत्वपूर्ण हितों को संतुलित किया है: जनता की संरक्षा, आपूर्तिकर्ताओं को आश्वासन और ऑपरेटरों का विश्वास। इसने दोष-रहित दायित्व सिद्धांत को प्रतिपादित किया और यह सुनिश्चित किया कि ऑपरेटर की ज़िम्मेदारी स्पष्ट और निर्देशित रहे। ऊर्जा परिदृश्य और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास ने संबंधित संस्थाओं की देनदारियों पर अधिक स्पष्टता को आवश्यक बना दिया है। इस तरह के संशोधन किसी भी परिपक्व क्षेत्र की स्वाभाविक प्रगति का हिस्सा हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि शासन का फ्रेमवर्क वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक अपेक्षाओं के साथ तालमेल बनाए रखे। नए अधिनियम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शासन का फ्रेमवर्क निष्पक्ष, स्पष्ट हो और संदेह रहित बना रहे, साथ ही जवाबदेही की एक सुपरिभाषित श्रृंखला भी बनाए रखे। इसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि दायित्व का मूल्यांकन करने की व्यवस्था देश में परमाणु तैनाती की सीमा और पैमाने के अनुरूप हो। एक आधुनिक दायित्व व्यवस्था को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि संरक्षा और ज़िम्मेदारी विकास के साथ-साथ चलती हैं।

जन विश्वास - प्रगति की आधारशिला

दुनिया भर में परमाणु उद्योग के उत्कृष्ट संरक्षा रिकॉर्ड के बावजूद, परमाणु ऊर्जा के प्रति जनता का दृष्टिकोण अक्सर वैज्ञानिक तथ्यों की तुलना में धारणाओं से अधिक प्रभावित होता रहा है। कुछ साल पहले मैंने जिस पुस्तक का सह-लेखन किया था, "द अनरीज़न्ड फियर ऑफ़ रेडिएशन",

ऐसी ही भ्रांतियों को दूर करने का एक प्रयास था। यह पुस्तक बताती है कि नियंत्रित और सुव्यवस्थित वातावरण में विकिरण, किसी भी अन्य तकनीक जितना ही सुरक्षित है जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में नियमित रूप से आत्मविश्वास से करते हैं। यदि नया अधिनियम नागरिकों के साथ खुले संवाद को बढ़ावा दे पाता है, तो यह समाज के साथ विज्ञान के सामाजिक संबंधों को पुनर्परिभाषित करेगा। ऐसा करके, यह हमारे चिरस्थायी आदर्श वाक्य: राष्ट्र की सेवा में परमाणु, की भावना को साकार करेगा। नए अधिनियम से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार के संदेश सार्वजनिक प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाएं, शैक्षिक जागरूकता को प्रोत्साहित करें तथा नागरिकों के साथ संवाद को संस्थागत कार्य प्रणाली का अभिन्न अंग बनाएं।

नए अधिनियम में क्या गारंटी होनी चाहिए

यदि 1962 के प्रथम परमाणु ऊर्जा अधिनियम ने क्षमता निर्माण के मूल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था, तो नए अधिनियम का उद्देश्य आत्मविश्वास बढ़ाना और परमाणु प्रौद्योगिकी की बड़े पैमाने पर तैनाती करना होना चाहिए। इसमें उस राष्ट्र की परिपक्वता प्रतिबिंबित होनी चाहिए जिसने जटिल तकनीकों में महारत हासिल की है और जिम्मेदार आचरण के माध्यम से वैश्विक सम्मान अर्जित किया है। नए अधिनियम को विज्ञान और समाज के बीच पारस्परिक आश्वासन की यह गारंटी देनी चाहिए कि:

- संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी,
- दायित्व (देनदारियां) हमेशा न्यायसंगत और पारदर्शी रहेगा, और
- जनता का विश्वास हर निर्णय के केंद्र में रहेगा।

जब ये गारंटियां न केवल कानून में, बल्कि संस्थागत व्यवहार में भी निहित होंगी, तो भारत का परमाणु भविष्य सुदृढ़ आधार पर खड़ा होगा।

विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम

भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए यह एक परिवर्तन का दौर है। बड़े विद्युत संयंत्रों के अलावा, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और प्रगत थोरियम प्रणालियाँ परमाणु ऊर्जा की पहुँच का विस्तार करेंगी। इसलिए नए अधिनियम को एक ऐसे फ्रेमवर्क की गारंटी देनी चाहिए जो प्रौद्योगिकियों के तेज़ उपयोग को सुगम बनाए और साथ ही स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण को प्रोत्साहित करे। इसमें नियामकों, प्रचालकों और उद्योग के बीच निर्बाध समन्वय और भविष्य के नवाचारों को शामिल करने के लिए लचीलापन सुनिश्चित करना चाहिए। संक्षेप में, नए अधिनियम को परमाणु पुनर्जागरण के लिए एक अनुकूल पृष्ठभूमि तैयार करनी चाहिए जो भारत में जलवायु लक्ष्यों और विकसित भारत @2047 बनने की राह में स्वच्छ-ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को विश्व का अग्रणी देश बनने की आकांक्षाओं के अनुरूप हो।

(लेखक पूर्व सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं पूर्व अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग)

सुशील भोले

कोंदा-भैरा के गोठ

-रायपुर रेलवे स्टेशन म काली छै झन नाबालिग लइका मन ल मानव तस्कर के फाँदा ले छोड़ाए गिस जी भैरा.

-हव जी कोंदा.. महूँ ल एकर आरो जनाए रिहिसे.. कोलकाता ले लेगत रिहीन हें लइका मनला रेल म मजदूरी कराए बर मुंबई.. फेर मोला सबले ताज्जुब के बात ए लागिस संगी के वो लइका मन के दाई-ददा मन सिरिफ पाँच-पाँच हजार रुपिया झोंक के ही वो मनला खुदे मजदूरी करे खातिर पठो दिए रिहीन हें.

-हव भई.. लइका मनला प्रशासन द्वारा इहाँ मुआवजा देके वापिस उँकर दाई-ददा तीर पठोए के उदिम होवत हे बताथें.

-हव जी.. फेर सवाल ए बात के हे संगी के का वो लइका मनला उँकर सियान मन फेर मजदूरी म नइ ढकेल देहीं?

-तोरो कहने सही हे.. जे लइका मन के पढ़ई लिखई ल छोड़वा के एक पइत पाँच हजार के लालच म मजदूरी खातिर भेज दिए गिस का वो मनला दुसरइया बेर नइ भेजे जा सकही?

-बिल्कुल भेजे जा सकथे.. मोला अइसे लागथे संगी के शासन ल कुछू अइसन रद्दा निकालना चाही जेकर ले लइका मन आसानी के साथ पढ़ई लिखई कर सकँय.. उनला बाल मजदूरी खातिर बरपेली ढकेले झन जा सकय.

चिंतन - डिजिटल अरेस्ट नहीं स्पिरिचुअल अरेस्ट हों...

बड़े-बूढ़ों को समझना पड़ेगा कि डिजिटल लाइफ अब टाइम पास नहीं रहा। इसका व्यवस्थित प्रशिक्षण उन्हें दिया जाना चाहिए। पुरानी कहावत है कि वेश्या के कोठे पर नाच-गाना देखने वाले ये बात जानते थे कि ये अपराध का अड्डा है। और जिस दिन अपराध घटेगा, नाच देखने का शौक महंगा पड़ जाएगा। ये डिजिटल दुनिया बिल्कुल ऐसी ही हो गई है।

8 हजार करोड़ से अधिक के अपराध डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से हो चुके हैं और खास तौर पर शिकार बड़े-बूढ़े ही बने। हमारे देश का आंकड़ा हमें बता रहा है कि समय आ गया है नए बच्चों की तरह इन पुराने लोगों को भी समझाना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा। अच्छा तो यह है कि डिजिटल अरेस्ट होने के पहले स्पिरिचुअल अरेस्ट होना समझ लें। जैसे-जैसे उम्र बढ़े, ईश्वर से अधिक जुड़ो।

इसके लिए आंख बंद करके, भीतर उतरकर अपनी आत्मा को स्पर्श करना पर्याप्त है। और ऐसा स्पिरिचुअल अरेस्ट सुख ही देगा। वरना दु:ख देने के लिए तो छोटा खिलौना हाथ में आ ही चुका है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेसी जनसैलाब

खरगे बोले- भाजपा-आरएसएस वोट चोरी कर देश से गद्दारी कर रही,संविधान को कमजोर कर रही

राहुल बोले- भाजपा के डीएनए में वोट चोरी, हमारे में सच्चाई, बेरोजगारी, महंगाई, नोटबंदी, गलत जीएसटी

प्रियंका गांधी ने दी चुनौती- भाजपा एक बार बैलेट पेपर पर निष्पक्ष चुनाव लड़ ले, वह कभी नहीं जीत पाएगी

शहर सत्ता/रायपुर/नई दिल्ली। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' महारैली को जनता का अभूतपूर्व समर्थन देखने को मिला। महारैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने चुनावों में हो रही धांधली को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत को पुरजोर तरीके से उजागर किया। कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे के बावजूद महारैली को समर्थन देने आए जनसैलाब को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि आज वोट चोरी कर जनता के मताधिकार पर हमला हो रहा है। यदि वोट डालने का अधिकार छिन गया तो गरीब और कमजोर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा वोट चोरी कर देश से गद्दारी कर रही है, इन्हें सत्ता से हटाना होगा।

रामलीला मैदान के अंदर और बाहर मौजूद भारी भीड़ के बीच उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए आगे कहा कि यह देश संविधान को मानने वाली कांग्रेस की विचारधारा से ही चल सकता है। मनुस्मृति को मानने वाली भाजपा-आरएसएस की विचारधारा से देश खत्म हो जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि भाजपा-आरएसएस संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुत्व के नाम पर गरीबों को गुलामी में रखने का प्रयास हो रहा है। वोट चोरी से आक्रोशित जनता के गगनभेदी नारों के बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने धाराप्रवाह संबोधन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान पर जमकर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अंततः सत्य नहीं, बल्कि शक्ति मायने रखती है। राहुल गांधी ने कहा कि यही वह विचारधारा है जो भाजपा को चला रही है, क्योंकि उनके लिए सत्ता के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और सभी धर्मों की मूल भावना सत्यम् शिवम् सुंदरम् व सत्यमेव जयते है, लेकिन आरएसएस की विचारधारा शक्ति को सत्य से ऊपर रखती है। उन्होंने कहा कि देश में सत्य और असत्य के बीच सीधी लड़ाई चल रही है। कांग्रेस सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए भाजपा को सत्ता से हटाएगी।

राहुल ने दिखाया आक्रामक अंदाज, चुनाव आयुक्तों पर मढ़ा आरोप

अपने आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी का नाम लेकर कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग की मदद से वोट चोरी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कानून बनाया है कि गड़बड़ी करने पर भी चुनाव आयुक्तों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर यह कानून बदलेगी और चुनाव आयुक्तों पर कड़ी कार्रवाई हो सकेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर हुई धांधली का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि एक ब्राजील मॉडल का फोटो 20 बार वोटर लिस्ट में पाया गया, एक ही पोलिंग बूथ पर एक महिला की फोटो 200 बार आई और उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता हरियाणा में वोट डालते पाए गए। लेकिन इन गंभीर सवालों पर चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। वोट चोरी के खुलासों के बाद भाजपा नेताओं की झल्लाहट की ओर इशारा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संसद में वोट चोरी के आरोपों का बचाव करते समय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा कि अमित शाह सत्ता में रहते हुए बहादुर बनते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता जाएगी, उनकी बहादुरी भी निकल जाएगी।

ऑस्ट्रेलिया में यहूदी फेस्टिवल के दौरान बीच पर अंधाधुंध फायरिंग, 10 की मौत

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर रविवार (14 दिसंबर, 2025) को यहूदी फेस्टिवल के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की घटना हुई. दो हथियारबंद हमलावरों ने वहां हजारों की संख्या में मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं. इस मास शूटिंग में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है. कहा जा रहा है कि रविवार का दिन होने की वजह से बीच पर भारी संख्या में लोग जुटे थे. ऑस्ट्रेलियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, यहूदियों की तादाद अच्छी खासी थी. ये सभी यहां पर आठ दिवसीय पवित्र पर्व हनुका के पहले दिन के समारोह के लिए एकत्रित हुए थे.

पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर शूटर्स को पकड़ा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, काले कपड़ों में दो लोगों ने राइफल्स या शॉटगन से ताबड़तोड़ फायरिंग की. 12 से 50 तक गोलियां चलने की आवाजें सुनी गईं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के एक दैनिक अखबार द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने इस गोलीबारी में 10 लोगों की मौत की पुष्टि की है.वहीं, सिडनी पुलिस ने तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दो संदिग्धों को हिरासत में लिया. स्थानीय मीडिया सिडनी संडे मॉर्निंग हेराल्ड के अनुसार, एक को पुलिस ने गोली मारी, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है. इलाके को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।

BJP की स्थापना के बाद पैदा होने वाले पहले अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन

नई दिल्ली। बीजेपी ने अपने नए लेकिन कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा बिहार के पीडब्ल्यूडी मंत्री नितिन नबीन को सौंपी है. नितिन नबीन वर्तमान में 45 साल के हैं. वह ऐसे पहले अध्यक्ष हैं, जो इतनी कम उम्र में अध्यक्ष बने हैं. नितिन नबीन पहले ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं, जो बीजेपी के स्थापना दिवस के बाद पैदा हुए थे. इससे पहले तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की स्थापना के पहले जन्म लेने वाले रहे हैं. बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और नितिन नबीन का जन्म 1 सितंबर 1980 में हुआ था.

पार्टी के 15वें अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन

बीजेपी की स्थापना के बाद सबसे पहले अध्यक्ष 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी बने थे. उनके बाद 1986 में दूसरे अध्यक्ष एलके आडवाणी बने. तीसरे अध्यक्ष 1991 में मुरली मनोहर जोशी बने. चौथे अध्यक्ष 1993 में एलके आडवाणी बने. पांचवे अध्यक्ष 1998 में कुशाभाऊ ठाकरे बने. छठे अध्यक्ष 2000 में बंगारू लक्ष्मण बने.बंगारू लक्ष्मण के बाद 2001 में जन कृष्णमूर्ति को जिम्मेदारी मिली. उनके बाद 2002 वेंकैया नायडू अध्यक्ष बने. 2004 में पार्टी की बागडोर एक बार फिर एलके आडवाणी ने संभाली. 2005 में राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया गया।

1947 के बाद पहली बार पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाई जाएगी संस्कृत

नई दिल्ली। विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान में संस्कृत भाषा को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है.

लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज (LUMS) ने इस शास्त्रीय भाषा में चार क्रेडिट का कोर्स शुरू किया है. यह पहल तीन महीने चलने वाले वीकेंड वर्कशॉप से विकसित हुई, जिसे छात्रों और विद्वानों से अच्छा प्रतिसाद मिला. कोर्स के तहत छात्रों को महाभारत टेलीविजन श्रृंखला के प्रसिद्ध थीम 'है कथा संग्राम की' का उर्दू संस्करण भी पढ़ाया जा रहा है. गुरमानी सेंटर के निदेशक डॉ. अली उस्मान कासमी ने द ट्रिब्यून को बताया कि पाकिस्तान के पास पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में सबसे समृद्ध, लेकिन सबसे अधिक उपेक्षित संस्कृत संग्रह हैं. उन्होंने कहा, 'संस्कृत ताड़ पत्र पांडुलिपियों का एक महत्वपूर्ण संग्रह 1930 के दशक में विद्वान जेसीआर वूल्नर द्वारा सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन 1947 के बाद से कोई पाकिस्तानी विद्वान इस संग्रह से जुड़ा नहीं.

पहली बार पूरी तरह डिजिटल होगी जनगणना, जाति गणना भी होगी शामिल, 30 लाख कर्मियों की तैनाती

भारत की जनगणना 2027 कराने की योजना को मंज़ूरी

शहर सत्ता/रायपुर नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 कराने की योजना को मंज़ूरी दे दी है। यह देश की 16वीं जनगणना और आज़ादी के बाद की आठवीं जनगणना होगी। इस महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रिया पर कुल 11,718.24 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय आएगा। सरकार के अनुसार यह जनगणना प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक नीति निर्माण के लिए एक मज़बूत आधार प्रदान करेगी।

दो चरणों में होगी जनगणना

जनगणना 2027 को दो चरणों में संपन्न किया जाएगा। पहले चरण में मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच की जाएगी। इसके बाद जनसंख्या गणना (Population Enumeration) फरवरी 2027 में होगी। हालांकि लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ़ से ढके एवं विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्या गणना सितंबर 2026 में ही पूरी कर ली जाएगी।

डिजिटल माध्यम से जनगणना

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना 2027 पूरी तरह डिजिटल होगी। डेटा संग्रह के लिए एंड्रॉयड और आईओएस आधारित मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जाएगा। साथ ही पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए Census Management & Monitoring System (CMMS) नामक समर्पित पोर्टल विकसित किया गया है, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी और डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 30 अप्रैल 2025 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया था कि आगामी जनगणना में जाति गणना को भी शामिल किया जाएगा। इसके तहत जनगणना 2027 के दूसरे चरण, यानी जनसंख्या गणना के दौरान जाति से संबंधित आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्र किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे सामाजिक और जनसांख्यिकीय विविधताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। इस विशाल राष्ट्रीय अभियान के लिए लगभग 30 लाख फील्ड कार्मिकों की तैनाती की जाएगी। इनमें गणनाकर्मी, पर्यवेक्षक, मास्टर ट्रेनर, चार्ज अधिकारी और जिला जनगणना अधिकारी शामिल होंगे। अधिकतर गणनाकर्मी सरकारी शिक्षक होंगे।

तीसरे टी20 में भारत की धमाकेदार जीत

गेंदबाजों ने ढाया कहर फिर अभिषेक शर्मा की आई आंधी

भारत ने तीसरे टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया है. धर्मशाला में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीकी टीम को 117 रनों पर ऑलआउट कर दिया. इसके जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने 25 गेंद शेष रहते लक्ष्य को हासिल कर लिया. इसी के साथ पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारत 2-1 से आगे निकल गया है.

118 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने तेजतर्रार शुरुआत दिलाई थी. गिल-अभिषेक ने मिलकर 5 ओवर में भारत को 60 रनों पर पहुंचा दिया था. अभिषेक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में एडन मार्करम को कैच थमा बैठे. उन्होंने 18 गेंद में 35 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 3 छक्के और 3 चौके निकले. अभिषेक शर्मा जब आउट हुए, तब 5.2 ओवरों में भारत 60 रन बना चुका था. उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने कछुए की चाल जैसे रन बनाए. पहले 5 ओवरों में टीम इंडिया 12 के रन रेट से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रही थी. अगले 40 रन बनाने यानी 60-100 रन तक पहुंचने के लिए भारतीय बल्लेबाजों ने 53 गेंद खेलीं.

गिल-सूर्या पर फिर उठेंगे सवाल!

टी20 टीम के उपकप्तान शुभमन गिल ने मैच में 28 रन बनाए, लेकिन इसके लिए उन्होंने 28 गेंद भी खेलीं. 18 पारियों के बाद भी शुभमन गिल का टी20 में अर्धशतक का इंतजार जारी है. दूसरी ओर कप्तान सूर्यकुमार यादव एक बार फिर 10 रन के पार पहुंचे, लेकिन इस बार भी उनके बल्ले से बड़ी पारी नहीं निकल पाई. सूर्या 12 रन बनाकर आउट हो गए.

भारतीय गेंदबाजों का कहर

धर्मशाला में पहले भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाते हुए दक्षिण अफ्रीकी टीम को 117 रन पर समेट दिया था. अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने दो-दो विकेट लिए. हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे भी एक-एक विकेट लेने में कामयाब रहे. इस मैच में हार्दिक पांड्या ने अपने टी20 करियर में बतौर गेंदबाज 100 विकेट पूरे कर लिए हैं.

मेसी-सचिन को एकसाथ देख झूम उठा वानखेड़े

खेल जगत में '10 नंबर जर्सी' को पहचान दिलाने वाले 2 दिग्गज एथलीटों की मुलाकात हुई है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर और लियोनेल मेसी एक-दूसरे से मिले और सचिन ने अपनी क्रिकेट जर्सी मेसी को भेंट भी की. यह क्रिकेट और फुटबॉल इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण रहा.

लियोनेल मेसी ने वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान सुनील छेत्री से भी मुलाकात की. वो उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस से मिले और उसके बाद 'मास्टर ब्लास्टर' सचिन तेंदुलकर से मिले. दोनों ने कुछ देर बाद भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है. सचिन तेंदुलकर ने अपनी 2011 वनडे वर्ल्ड कप वाली जर्सी मेसी को भेंट की. वहीं अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर ने 2022 वर्ल्ड कप वाली बॉल सचिन तेंदुलकर को भेंट की. सचिन तेंदुलकर क्या कह रहे थे, इसके लिए मेसी के साथ उनकी ट्रांसलेटर भी मौजूद थी.

सचिन ने की मेसी के समर्पण की तारीफ

इसी बीच सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि उनका लियोनेल मेसी के भारत आने पर क्या सोचना है. उन्होंने कहा, "हम लियोनेल मेसी की समर्पण, दृढ़ता और प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं. विनम्र स्वभाव के लिए, वो जिस तरह के इंसान हैं, उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है. मुंबई और भारत के लोगों की तरफ से मैं मेसी और उनके परिवार को खुश रहने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं."

आईपीओ लाने की तैयारी में Shiprocket

नई दिल्ली। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कंपनी शिपरॉकेट (Shiprocket) अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है. इसके लिए कंपनी ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के पास अपना अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस-I (UDRHP-I) जमा कराया है. शिपरॉकेट के आईपीओ का साइज 2,342.3 करोड़ रुपये है. अपडेटेड DRHP के मुताबिक, IPO में 1,100 करोड़ रुपये के फ्रेश इश्यू जारी किए जाएंगे और ऑफर फॉर सेल (OFS) भी रहेगा, जिसके जरिए मौजूदा शेयरहोल्डर्स 1,242.3 करोड़ रुपये तक के शेयर बेचेंगे. इससे पहले कंपनी ने मई 2025 में कॉन्फिडेंशियल रूट से सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा कराए थे, जिसे नवंबर में मंजूरी मिली थी. इससे पहले कंपनी ने मई 2025 में कॉन्फिडेंशियल रूट से सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा किए थे, जिसे नवंबर में मंजूरी मिली थी. इसके बड़े इन्वेस्टर्स में Eternal Limited (पहले Zomato Limited) हैं, जिसके पास 6.85 परसेंट की हिस्सेदारी है।

अंडमान सागर में मिला मिथेन का भंडार

नई दिल्ली। अमेरिकी टैरिफ, H-1B की बढ़ाई गई फीस और व्यापार वार्ता को लेकर जारी अनिश्चितताओं के बीच भारत के लिए एक 'गुड न्यूज' है. दरअसल, अंडमान सागर में नैचुरल गैस का बड़ा भंडार हाथ लगा है. यह खोज किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है. इससे भारत एनर्जी सेक्टर में भारत और मजबूत व आत्मनिर्भर बनेगा.शुक्रवार को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका ऐलान किया. इस दौरान उन्होंने इसे 'ऊर्जा के अवसरों' का सागर बताया. उन्होंने कहा, प्राकृतिक गैस की यह खोज अमृत काल के हमारे इस सफर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी.

कहां मिला नैचुरल गैस का भंडार?

नैचुरल गैस का यह रिजर्व के विजयपुर के 2 कुएं में पाया गया, जो अंडमान तट से लगभग 17 किलोमीटर दूर 295 मीटर की गहराई पर स्थित है. इसकी लक्षित गहराई 2650 मीटर रखी गई थी. यानी कि कुएं को पानी की सतह से लेकर समुद्र के नीचे जमीन में कुल 2650 मीटर की गहराई तक खोदा गया था. पहले 295 मीटर की गहराई तक खोदे जाने पर नैचुरल गैस रिजर्व का जैकपॉट हाथ लगा. इसके बाद लगभग 2355 मीटर की गहराई तक और ड्रिल किया गया. पुरी ने कहा, "कुएं के 2212 से 2250 मीटर की गहराई तक किए गए शुरुआती उत्पादन परीक्षण से नैचुरल गैस के होने का पता चला. इसमें समय-समय पर फ्लेयरींग होते भी भी देखी गई. गैस के नमूने जहाज से काकीनाडा लाए गए, उनकी टेस्टिंग की गई और पाया गया कि उनमें 87 परसेंट मीथेन है." आने वाले महीनों में गैस पुल की साइज और कमर्शियली यह कितना मददगार साबित होगा इसका पता लगाया जाएगा।

क्रिप्टो बाजार में हड़कंप! बिटकॉइन-एथेरियम फिसले

नई दिल्ली। क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में बहुत तेजी से उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. शनिवार, 13 दिसंबर 2025 को क्रिप्टोकरेंसी बाजार एक बार फिर फिसल गया. इसमें रिकॉर्ड गिरावट देखी जा रही है. कॉइनमार्केटकैप के अनुसार, क्रिप्टो बाजार 2.01 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3.06 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई है. दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन में पिछले 24 घंटे में करीब 2.24 फीसदी की गिरावट दर्ज की जा रही है. अमेरिकी फेड के द्वारा ब्याज दरों में कटौती की घोषणा के बाद क्रिप्टोकरेंसी बाजार में तेजी आई थी. हालांकि, ये तेजी ज्यादा दिनों तक नहीं रही और फिर से क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट शुरू हो गई। कॉइनमार्केटकैप के अनुसार, सुबह करीब 10:38 बजे बिटकॉइन 90,390.35 डॉलर पर कारोबार कर रही थी. जो पिछले 24 घंटे में 2.24 प्रतिशत की गिरावट को दिखाता है. हालांकि, पिछले 7 दिनों के आंकड़ों की बात करें तो, बिटकॉइन में करीब 0.75 प्रतिशत की तेजी है.

कच्छ में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट

नई दिल्ली। गुजरात के कच्छ में खावड़ा के रेगिस्तानी इलाके में गौतम अडानी की अगुवाई वाली कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगा रही है. 538 स्क्वॉयर किलोमीटर में फैले इस प्लांट का जिक्र गौतम अडानी के भतीजे और अडानी एंटरप्राइजेज के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने टेलीविजन पर हाल ही में दिए अपने इंटरव्यू में किया. यह सोलर प्लांट पेरिस से भी पांच गुना बड़ा है, अब समझ लीजिए कि यह कितना विशाल है. कंपनी के क्लीन-एनर्जी प्रोजेक्ट की बात करते हुए उन्होंने इसका जिक्र किया. 2023 में इस प्लांट की शुरुआत की गई और इन्हीं दो सालों में इसने 5000 मेगावाट या 5 गीगावाट की कैपेसिटी भी हासिल कर ली. कंपनी का लक्ष्य आने वाले पांच सालों में इसकी कैपेसिटी को 30 गीगावाट तक पहुंचाना है.प्रणव अडानी ने इस प्रोजेक्ट को इतना बड़ा बताया कि भविष्य में यह चांद से भी दिख सकता है।

25000 टन सोने के मालिक हैं भारतीय परिवार

नई दिल्ली। भारत में सोने का क्रेज ही अलग है.आलम यह है कि यहां बिना सोने-चांदी के गहने के शादी अधूरी मानी जाती है. कई बार लोग एक-दूसरे को किसी मौके पर सोने के छोटे-मोटे गहने भी गिफ्ट करते हैं. भारत में सोने को शुभ माना जाता है. इसके अलावा, सुरक्षित निवेश के रूप में भी इसकी डिमांड काफी ज्यादा है. सोने को लेकर इसी दिवानगी का नतीजा हैकि भारतीय परिवारों के पास लगभग 25,000 टन सोना है और यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. इसी के साथ भारतीय परिवारों के पास दुनिया का सबसे अधिक सोना है. सोने के प्रति भारतीयों के इसी लगाव का जिक्र करते हुए एक रिसर्च एनालिस्ट ने बीते मार्च के महीने में एक चौंकानेवाले डेटा का खुलासा किया. इसके मुताबिक, भारत में लोगों की संपत्ति में महज एक साल में सोने के जरिए ही लगभग 750 बिलियन डॉलर का उछाल आया. इससे पता चलता है कि देशभर में बीते एक साल में सोने की किनी खरीदारी हुई. एक पोस्ट के जरिए एनालिस्ट ए के माधवन ने बताया कि भारत का प्राइवेट गोल्ड रिजर्व 25,000 टन है, जो अमेरिका, जर्मनी, चीन और यहां तक कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है.

भारत सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार

बता दें कि अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस, चीन, स्विट्जरलैंड, भारत, जापान और तुर्की के पास जैसे देशों के सेंट्रल बैंकों के पास रखा टोटल गोल्ड रिजर्व भी भारतीय परिवारों के पास मौजूद सोने के बराबर नहीं है. इससे पता चलता है कि भारत में लोग सेविंग्स या इंवेस्टमेंट के नजरिए से सोने को कितना अहम मानते हैं. गोल्ड हमेशा से भारत में लोगों का पसंदीदा रहा है क्योंकि महंगाई, आर्थिक अनिश्चितता और मुद्रा में उतार-चढ़ाव के बीच यह ढाल के रूप में काम करता है. शादियों के मौसम में या फेस्टिव सीजन में इसकी डिमांड और भी बढ़ जाती है. गांव में लोग सोने का इस्तेमाल कई बार बैंकों में गिरवी रखने और अपनी जरूरतों को पूरा करने में करते हैं. सोने की कीमतों में वैश्विक उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता बना हुआ है.

भारत की डिफेंस कंपनी को इस्राईल से मिला करोड़ों का ऑर्डर

नई दिल्ली। भारत की पारस डिफेंस एंज स्पेस टेक्नोलॉजीज कंपनी (PARAS) को इज़राइल की एल्बिट सिक्योरिटी सिस्टम्स लिमिटेड से लगभग 34 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है. कंपनी को इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स की सप्लाई के लिए यह ऑर्डर मिला है. जानकारी मिली है कि कंपनी इस ऑर्डर को फरवरी 2026 से नवंबर 2026 के बीच पूरा करनी की योजना बना रही है. एक ओर जहां ट्रंप के टैरिफ, H-1 वीजा और फॉर्मा कंपनियों पर लगाए गए टैरिफ के कारण भारतीय शेयर बाजार में हलचल है, वहीं शुक्रवार को इस अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर से कंपनी के शेयरों में एक प्रतिशत से अधिक की उछाल देखी गई. सोमवार, 29 सितंबर को भी इसके शेयर फोकस में रह सकते हैं. पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज कंपनी का मार्केट कैप 55.96 बिलियन का है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

जनता की आस्था ही सरकार की सबसे बड़ी शक्तिः साय

छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के दो साल पूरे, सीएम साय ने दिया जनता को संदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने अपने दो साल पूरे कर लिए हैं। इन दो सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कामकाज अच्छा रहा है। सरकार के दो साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने कार्यकाल और अनुभव को सोशल मीडिया के जरिए साझा किया है। सीएम साय ने अपने संदेश में लिखा, प्रिय छत्तीसगढ़वासी भाइयों और बहनों, जय जोहार, आज जब मैं सेवायात्रा के दो वर्ष पूरे कर रहा हूं, तो मन अपार भावनाओं से भर गया है। यह दो वर्ष मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष रहे, क्योंकि यह समय केवल शासन का नहीं, सेवा और समर्पण का था। आपके साथ चलने का, आपकी मुस्कान में अपने दायित्व का प्रतिबिंब देखने का अवसर मिला।

छत्तीसगढ़ विश्वास और स्थिरता के एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा

मुख्यमंत्री ने कहा, प्रशासन और लोगों के बोद जो दूरी कमी रही, वह अब सहभागिता में बदल रही है। मुझे गर्व है कि छत्तीसगढ़ आज विश्वास और स्थिरता के एक बर अध्याय की ओर बढ़ रहा है। भविष्य के लिए हमारी प्रतिबद्धता और भी सशक्त है।

आने वाले वर्षों में हम शिक्षा, रोजगार, कृषि और ग्रामीण विकास पर और तीठ गति से काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है ऐसा छत्तीसगढ़, जो आत्मनिर्भर हो, जहा हर युवा को अवसर मिले, किसान को गर्व हो और हर नागरिक को यह विश्वास हो कि उसका शासन उसके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा, प्रिय जनों, यह यात्रा अभी लंबी है और मंजिल बड़ी। मैं आप सबसे यही अपेक्षा करता हूं कि इस विकास यात्रा में अपने सुझावों, अपने परिश्रम और अपने विश्वास से हमारा मार्ग रोशन करते रहें। आपकी आस्था ही हमारी शक्ति है, और आपका सहयोग ही छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य की गारंटी।

डिप्टी सीएम साव ने भी दी शुभकामनाएं

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, सीएम विष्णुदेव साय के बेतृत्व में धने हुए सरकार के 2 साल पूरा होवत हे में आप सब हान ला गाड्य गडा बधाई अउ सुभकामना देवत हथ। प्रतिबिंब देखने का अवसर मिला। इन दो वर्षों में हमने छत्तीसगढ़ के हर कोने में विकास का दीप जलाने की कोशिश की है। हमने किसानों की मेहनत को सम्मान देने के लिए सुविधाएं बढ़ाईं, जिससे उनकी उपज का पूरा मूल्य समय पर मिल सके।

शासन अब जनता के द्वार पर

युवाओं के भविष्य को बेहतर बनने के लिए नई अर्तियों, प्रशिक्षण और औद्योगिक्त अवसरों के द्वार खेले गए। आदिवासी अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों का ऐस जाल बिछाया गया जिससे विकास की रोशनी उत्रन इलाकों तक पहुंचे जहा पहले उम्मीदें धुंधली थीं। हमारी बहनें के लिए सुरक्षा और सम्मान की दिशा में नर कदम उठाए गए, तकि हर घर में आत्मविश्वास और स्वावलंबन का वातावरण बने। इन सभी प्रयासों के श्रीच सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि शासन अब जनत के द्वार पर है।

भाजपा सरकार 2 साल में ही अलोकप्रिय हो गईः बैज

साय सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल में जनता का भरोसा खे दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा सरकार के खिलाफ चौतरफा आक्रोश है। मोदी की गारंटी के नाम पर जनता का मत हासिल किया। 2 साल में एक भी मोदी की गारंटी पूरी नहीं की। सरकार से प्रदेश का हर वर्ग नाराज है। किसान और युवा नाराज है. सरकारी भर्तियां बंद हैं, जो मर्तियां हुई हैं, उसमें भ्रष्टाचार किया गया। आदिवासियों, किसनों की जमीने जबरिया उद्योगों और खदानों के लिये अधिग्रहित की जा रही हैं। महिलाएं निराश हैं महतारी वका के नाम पर उनसे धोखा किया गया। बिजली के दाम बढ़ाने, भूमि की गाइडलाइन के रेट बढ़ाने 5 डिसमिल से कम जर्मनों की रजिस्ट्री बंद करने से जनता वाराज है। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो सरकार के 2 साल के कार्यकाल से खुश हो। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार के 2 साल में छत्तीसगढ़ की जनता को निराश किया है। साय सरकार को उपलब्धि के नाम पर पिछली सरकार की योजनायें बंद करना मात्र है। साथ सरकार ने जनता के हित में चलाई जाने वाली योजनओं को दुर्भावनापूर्ण बंद किया। 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना बंद कर दिया, राजीव मितान योजना, मोधन व्याय योजना, शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक बीमा योजना, बेरोजगारी मता, रोपा, मुख्यमंत्री कर्ज माफी. सिंचाई कर माफी, महिला समूहों की ऋण माफी, सीएम आदिवासी परख सम्मान निधि, सीएम छत्तीसगढ़ी परख सम्मान निधि, कोदो, कुटकी, रागी खरीदी बरवा-गरवा-घुरता बारी, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, मुख्यमंत्री महतारी दुलार, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन, धरस विकास, शहरी गरीधों को पट्टा एवं आवास, छत्तीसगढ़यि ओलिपिक, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना को बंद किया।

घुसपैठिए के नाम पर काटे जा रहे विपक्षियों के वोटर

रायपुर। दिल्ली में कल कांग्रेस वोट चोर, गद्दी छोड़ रैली निकालेगी, जिसमें शामिल होने पीसीसी चीफ दीपक बैज दिल्ली रवाना हुए। उन्होंने एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से चर्चा में कहा, 14 दिसंबर को रामलीला मैदान पर रैली होगी। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया और प्रियंका गांधी समेत देशभर से तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। एसआईआर के विरोध में छत्तीसगढ़ से 5 हजार कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। एसआईआर पर बीजेपी के आरोप पर दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा, घुसपैठिए कहां से आए, कैसे आए, पहले यह बताएं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर घुसपैठिए कैसे आए। जहां-जहां चुनाव वहां घुसपैठिए के नाम पर नौटंकी की जा रही। बिहार में घुसपैठिए खत्म हो गए, अब असम बंगाल में रहेंगे। घुसपैठियों के नाम पर विपक्षियों के वोटर्स के नाम काटे जा रहे। गुलाब कमरो का नाम महेंद्रगढ़ से काटकर रायगढ़ में जोड़ दिए। बिलासपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष का नाम भिलाई में जोड़ रहे। यह सब साजिश है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान पर दीपक बैज ने जवाब देते हुए कहा, कांग्रेस खून पसीने से सींची हुई पार्टी है। कांग्रेस चुनाव में हार या प्रताड़ना से नहीं डरती।

कांग्रेस ने उठाया थर्ड जेंडर का एसआईआर फार्म में नाम का मुद्दा

शहर सत्ता/रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा थर्ड जेंडर एसआईआर फार्म में 2003 की मतदाता सूची में खुद का या माता-पिता के नाम की जानकारी भरने को लेकर परेशान है। चुनाव आयोग द्वारा मांगी जा रही दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण वो एसआईआर फार्म भर नहीं पा रहे है।

चुनाव आयोग बताए- थर्ड जेंडर का नाम बिना दस्तावेज मतदाता सूची में कैसे जुड़ेगा

थर्ड जेंडर एसआईआर फार्म नहीं जमा करने के कारण मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होने के बाद आने वाली समस्याओं को लेकर तनाव में है, ऐसे में चुनाव आयोग को उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिये। माननीय न्यायालय ने 2014 में थर्ड जेंडर की मान्यता दी है। उसके पहले थर्ड जेंडर का मतदाता सूची में पुरुष के रूप में दर्ज थे, अब उन्हें थर्ड जेंडर दर्ज कराने में परेशान है, माता-पिता पहले ही उन्हें त्याग दिए है, ऐसे में माता-पिता की जानकारी भी उनके पास नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि एसआईआर को लेकर थर्ड जेंडर के अलावा अन्य वर्ग को भी दस्तावेज जमा कराने में दिक्कत हो रही है। कई परिवार ऐसे है जिनकी माता-पिता की मृत्यु 2003 के पहले हो चुकी है। बस्तर में 2011 में नक्सली आतंक के कारण पलायन कर दूसरे राज्य चले गये है, उनका नाम कैसे जुड़ेगा? कई असहाय है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, अनाथालय में रहते है, गोद लिये गये बच्चे जो अब वयस्क हो गये है। इन सभी को फार्म भरने में कठिनाई हो रही है। कई परिवार ऐसे भी है जो वर्षों से छत्तीसगढ़ में रह रहे है, लेकिन रोजी मजदूरी के लिए बार-बार शहर बदलना पड़ा, उनका नाम कैसे जुड़ेगा? चुनाव आयोग को इनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए।

पहली सूची के अप्रैल में आने के बाद से ही दूसरी सूची का हो रहा है इंतजार

भाजपा नेताओं को अब निगम, मंडल में नए साल में ही कुर्सी मिलने की संभावना

रायपुर। प्रदेश के भाजपा नेताओं को निगम, मंडल, आयोग और बोर्ड में अब नए साल में ही कुर्सी मिलने की संभावना है। पहली सूची इस साल अप्रैल में नवरात्रि के समय आई थी। पहले संभावना जताई जा रही थी कि दूसरी सूची भी जल्द आएगी, लेकिन सूची के लिए इंतजार लंबा होता गया और चैत्र नवरात्रि में दूसरी सूची आने की बात सामने आई। अब तो नवरात्रि क्या दीपावली भी निकल गई पर अब तक दूसरी सूची नहीं आई है। वैसे दूसरी सूची के ज्यादातर पदों के लिए नामों पर मंथन हो गया है और राष्ट्रीय नेताओं के साथ चर्चा भी हो गई है, लेकिन सूची जारी कब होगी, यह किसी को मालूम नहीं है। अब यह संभावना जताई जा रही है जो होगा नए साल में ही होगा। प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष किरण देव की नई कार्यकारिणी के ऐलान के बाद अब जहां विधायकों की नजरें संसदीय सचिवों के पदों पर हैं, वहीं निगम, मंडल और आयोग में बचे पदों को लेकर भी भाजपा नेता इंतजार कर रहे हैं। इधर भाजपा के प्रदेश संगठन का विस्तार भी चल रहा है। ऐसे में कई नेताओं को यहां भी पद मिल रहे हैं। संगठन का विस्तार इस माह के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इसके बाद ही नए साल में निगम, मंडल, आयोग की कुर्सी बंटेगी।

संसदीय सचिवों की नियुक्ति भी बाकी

प्रदेश में भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल का लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री श्री साय के विदेश प्रवास पर जाने से पहले अगस्त में विस्तार हो चुका है। प्रदेश सरकार ने तीन नए मंत्री बनाए हैं। मंत्रिमंडल में जिनको स्थान नहीं मिल सका है, उन नए विधायकों की नजरें अब संसदीय सचिवों के पदों पर हैं। इनकी नियुक्ति भी अब नए साल में ही होने की संभावना है।

8 माह बाद सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं

जिन निगम, मंडलों में अभी नियुक्ति बाकी है उनमें मार्कफेड, लघु वनोपज सहकारी संघ, मत्स्य महासंघ, हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ, सिंधी अकादमी और सहकारी संघ शामिल हैं। इसी के साथ पांच जिलों के सहकारी केंद्रीय बैंक और चार शक्कर कारखानों में भी अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है। इसके अलावा रायपुर विकास प्राधिकरण, गृह निर्माण मंडल जैसे निगम, मंडलों में उपाध्यक्षों के साथ सदस्यों के पद भी खाली हैं। इनकी संख्या भी डेढ़ दर्जन से ज्यादा है। इनमें नियुक्ति के लिए भी आठ माह से इंतजार हो रहा है, लेकिन इसमें भी नियुक्ति नहीं हो सकी है।

छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047: विकसित छत्तीसगढ़ का रोडमैप

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा

शहर सत्ता/रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में छत्तीसगढ अंजोर विजन 2047 पर चर्चा करते हुए कहा कि यह विजन प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का स्पष्ट रोडमैप है। उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज आने वाले वर्षों में राज्य के विकास की दिशा तय करेगा। उन्होंने इस मौके पर विकसित छत्तीसगढ के निर्माण में सहभागी बनने के लिए सभी सदस्यों से आव्हान किया। उन्होंने इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए राज्य के अतीत, वर्तमान उपलब्धियों और भविष्य की दिशा पर प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा है। उनके अनुरूप हमने भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। विकसित छत्तीसगढ़ की यात्रा के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण चरण बनाये हैं। हमने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समय अवधि तय की है। जैसे वर्ष 2030 तक हम निकटवर्ती लक्ष्य हासिल करेंगे। इसी तरह साल 2035 तक मध्यवर्ती और 2047 तक लक्ष्य हासिल करेंगे।

अंजोर विजन में 13 क्षेत्रों को किया गया चिन्हांकित

छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डाक्यूमेंट जनभागीदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे तैयार करने के लिए हमने किसान, युवा, महिला, उद्यमी, कारोबारी समेत समाज के हर वर्ग से सुझाव मांगे। मुझे स्वयं उनसे प्रत्यक्ष बातचीत करने का मौका मिला। इस अंजोर विजन में हमने शिक्षा,

स्वास्थ्य, कृषि, अधोसंरचना जैसे 13 क्षेत्रों को चिन्हांकित कर इनके विकास के लिए 10 मिशन गठित करने का निर्णय लिया। हम ग्रामीण विकास के साथ.साथ अर्बन प्लानिंग के बेहतरीन मॉडल खड़े कर रहे हैं। नवा रायपुर भविष्य का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है। यह शहर मेडिकलए एजुकेशन, टेक्सटाइल, आईटी और एआई का ग्लोबल हब बनने जा रहा है। हम ग्रामीण विकास के साथ.साथ अर्बन प्लानिंग के बेहतरीन मॉडल खड़े कर रहे हैं। नवा रायपुर भविष्य का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है। यह शहर मेडिकल, एजुकेशन, टेक्सटाइल, आईटी और एआई का ग्लोबल हब बनने जा रहा है।

गरीबों, किसानों और वंचित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बीते वर्षों में गरीबों, किसानों और वंचित वर्गों के लिए अनेक योजनाएं चलाई गईं और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयास किए गए। उन्होंने बताया कि सरकार की पहली ही कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 18 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई। महिला सशक्तीकरण के लिए महतारी वंदन योजना एक ऐतिहासिक पहल बनी। लगभग 70 लाख माताओं-बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता दी जा रही है। डीबीटी के माध्यम से अब तक 22 किस्तों में 14 हजार 306 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज और वनोपज संग्राहकों के हित में तेंदूपत्ता पारिश्रमिक 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया है। 13 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। चरणपादुका योजना पुनः प्रारंभ की गई है तथा 73 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है।

इको-टूरिज्म, बस्तर पंडुम तथा बस्तर ओलंपिक से बनी बस्तर की पहचान

बस्तर में बस्तर ओलंपिक एवं बस्तर पांडुम जैसे कार्यकमों के माध्यम से बस्तर की आम जनता तक पहुंच रहे है।इस साल बस्तर पांडुम में इस बार 3 गुना लोगों के हिस्सा लेने का अनुमान है। जो हमारी सरकार की सफलता को दिखाती है।आइए इस ऐतिहासिक दिन में हम सभी संकल्प ले की प्रदेश की विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को पूरा करे। इको-टूरिज्म, बस्तर पंडुम तथा बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन नई पहचान बना रहे हैं।

8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त

श्री साय ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार और उद्योग के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। अब तक 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लॉजिस्टिक पार्क, एयर कार्गो सुविधा और औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा; बीएलओ ऐप से गणना पत्रक अपलोड अनिवार्य

शहर सत्ता/रायपुर। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री यशवंत कुमार की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूची के अद्यतन कार्य की विस्तार से समीक्षा की गई।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने सभी रजिस्ट्रीकरण निर्वाचन अधिकारियों (ERO) एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण निर्वाचन अधिकारियों (AERO) को निर्देशित किया कि अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में गणना पत्रकों का भौतिक परीक्षण कर बीएलओ ऐप के माध्यम से अनिवार्य रूप से अपलोड कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, उनके संबंध में आवश्यक प्रमाण सुरक्षित रखा जाए। श्री कुमार ने निर्देश दिए कि छूटे हुए सभी पात्र मतदाताओं का पुनरीक्षण सुनिश्चित किया जाए तथा ASD (अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत) श्रेणी के मतदाताओं का भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप सटीक सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही अप्राप्त गणना पत्रकों की सूची के संबंध में राजनीतिक दलों के बीएलए के साथ अनिवार्य रूप से समन्वय बनाकर कर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को मतदाता सूची के अद्यतन कार्य को अत्यंत संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिया।

रायपुर में धान खरीदी में अवैध वसूली कलेक्टर ने एक को किया बर्खास्त

शहर सत्ता/रायपुर। धान खरीदी में भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारी पर रायपुर कलेक्टर ने कार्रवाई की है। किसानों से अवैध वसूली के आरोप में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति नरदहा के एक कर्मचारी को तत्काल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर कार्रवाई की गई। किसानों की ओर से शिकायत मिली थी कि, समिति का कर्मचारी टोकन जारी करने और धान की गुणवत्ता में कमी बताने के नाम पर दबाव बनाकर पैसे की मांग कर रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने आरंग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को जांच के निर्देश दिए। जांच में आरोप सही पाए गए और यह स्पष्ट हुआ कि कर्मचारी ने किसानों से अनुचित तरीके से धन वसूली की।

जांच रिपोर्ट सामने आते ही उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायपुर ने कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए संबंधित कर्मचारी राकेश जांगड़े को नौकरी से हटा दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने की दिशा में कड़ा

रायपुर कलेक्टर गौरव की चेतावनी शिकायतें मिली तो होगा एक्शन

कदम है। जिला प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि, किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी, शोषण या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में इस तरह की शिकायतें सामने आती हैं, तो दोषियों पर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अवैध मांग या अनियमितता की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।

स्टाम्प व रजिस्ट्री शुल्क में नागरिकों को सीधा लाभ

जनहित में बड़ा फैसला: पेरी-अर्बन व अन्य ग्रामों में वर्ग मीटर दर समाप्त

शहर सत्ता/रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुसार वित्त एवं वाणिज्य कर पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भूमि मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पेरी-अर्बन ग्रामों एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में लागू वर्ग मीटर दर को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। अब ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में भूमि का मूल्यांकन केवल हेक्टेयर दर के आधार पर किया जाएगा। इस फैसले से आम नागरिकों, किसानों और भू-धारकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

पूर्व व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर तक की भूमि का मूल्यांकन वर्ग मीटर दर से तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक भूमि का मूल्यांकन हेक्टेयर दर से किया जाता था। चूंकि वर्ग मीटर दर, हेक्टेयर दर की तुलना में अधिक होती थी, इसलिए कम क्षेत्रफल वाली भूमि पर अधिक मूल्य और मुआवजा देय हो जाता था, जबकि बड़े क्षेत्रफल की भूमि पर अपेक्षाकृत कम। यह एक बड़ी विसंगति थी, जिसे समाप्त करते हुए सरकार ने अब सभी ग्रामीण भूमि के लिए एक समान हेक्टेयर आधारित मूल्यांकन व्यवस्था लागू की है।

इस निर्णय से भू-अर्जन प्रकरणों में अब भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल के अनुरूप न्यायसंगत मुआवजा मिल सकेगा। उदाहरण के तौर पर बालोद जिले के ग्रामीण क्षेत्र देवारभाट में पूर्व व्यवस्था के तहत 500 वर्ग मीटर भूमि का मूल्यांकन 9 लाख 25 हजार रुपये किया जाता था, जबकि 1000 वर्ग मीटर (0.10 हेक्टेयर)

भूमि का मूल्यांकन केवल 3 लाख 67 हजार रुपये होता था। नई व्यवस्था में वर्ग मीटर दर समाप्त होने के बाद 500 वर्ग मीटर भूमि का मूल्यांकन 6 लाख रुपये तथा 1000 वर्ग मीटर भूमि का मूल्यांकन 12 लाख रुपये किया जा रहा है, जो पूरी तरह तर्कसंगत और न्यायसंगत है।

वर्ग मीटर दर समाप्त होने से स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में भी उल्लेखनीय कमी आई है। भूमि का मूल्यांकन अब वास्तविक और किफायती दरों पर होने से रजिस्ट्री की कुल लागत घट रही है। इससे ग्रामीण एवं पेरी-अर्बन क्षेत्रों में भूमि खरीदना आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ हो गया है।

उप पंजीयक कार्यालय बालोद में 9 अक्टूबर 2025 को पंजीकृत एक दस्तावेज के अनुसार ग्राम देवारभाट में 15 डिसमिल भूमि के पंजीयन में पूर्व व्यवस्था के तहत बाजार मूल्य 7 लाख 90 हजार रुपये आंका गया था, जिस पर 74 हजार 900 रुपये स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क देय था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद उसी भूमि का बाजार मूल्य 4 लाख 80 हजार रुपये निर्धारित हुआ और पक्षकारों द्वारा मात्र 45 हजार 500 रुपये स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क अदा किया गया। इस प्रकार संबंधित पक्षकारों को सीधे 29 हजार 400 रुपये का लाभ हुआ।

सरकार के इस फैसले से किसानों, भू-धारकों और आम खरीदारों को अनावश्यक अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी। साथ ही भूमि लागत कम होने से रियल एस्टेट, आवास निर्माण और विकास कार्यों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मूल्यांकन प्रक्रिया के सरलीकरण से नियमों की जटिलता कम हुई है और आमजन के लिए प्रक्रिया अधिक सहज एवं पारदर्शी बनी है।

राज्य सरकार का यह निर्णय ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी जनता के हित में दूरगामी प्रभाव वाला कदम है, जिससे हजारों लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। सरकार का उद्देश्य भूमि एवं आवास से जुड़ी प्रक्रियाओं को सुलभ, किफायती और जनकल्याणकारी बनाना है और यह सुधार उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

धुरंधर की आंधी

रणवीर सिंह की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बनाए 5 रिकॉर्ड

- धुरंधर ने 9 दिनों में ही 300 करोड़ छूने वाला माइलस्टोन क्रॉस किया.
- इसके अलावा फिल्म सेकंड वीक में एक दिन में 50 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है धुरंधर.
- हिस्ट्री की दूसरे शनिवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है धुरंधर.
- दूसरे शनिवार को फिल्म ने पहले शनिवार, शुक्रवार और रविवार से ज्यादा कमाई की है.
- इसके अलावा फिल्म के दूसरे रविवार को 60 करोड़ की कमाई करने की उम्मीदें हैं.

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म ने 9 दिनों में 300 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है. फैंस में फिल्म को लेकर बहुत क्रैज देखने को मिल रहा है. शोज हाउसफुल जा रहे हैं और इसी वजह से मिड नाइट शोज भी ओपन किए गए हैं. फिल्म क्रिटिक जोगिंदर टुटेजा ने बताया कि फिल्म ने 9 दिन में ही 5 नए रिकॉर्ड बना लिए हैं.

बता दें कि इस फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. आदित्य धर को फिल्म उरी के लिए भी जाना जाता है. आदित्य की स्टोरी टेलिंग फैंस को बहुत पसंद आती है. धुरंधर में भी आदित्य ने कमाल कर दिया है. उनके काम की हर तरफ तारीफ हो रही है. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं और अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे स्टार्स भी नजर आ रहे हैं.

सभी ने कमाल का काम किया है. फिल्म में सारा अर्जुन फीमेल लीड में हैं. इसके अलावा सौम्या टंडन, गौरव गेरा, क्रिस्टल डीसूजा, आयशा खान जैसे स्टार्स भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. आयशा और क्रिस्टल ने तो फिल्म में आइटम नंबर किया है. फिल्म का अब दूसरा पार्ट भी आना है. फिल्म का दूसरा पार्ट मार्च 2026 में आएगा. फैंस इसके लिए बेसब्र हैं.

'धुरंधर' के खिलाफ पाकिस्तान ने अनाउंस की फिल्म 'मेरी लयारी'

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है. एंटी पाकिस्तानी फिल्म के चर्चे पाकिस्तान तक पहुंच गए हैं. पाकिस्तानी इस फिल्म को नेटेगिव प्रोपेगेंडा वाली फिल्म बता रही है. इस बीच पाकिस्तान ने 'धुरंधर' में पाकिस्तान की लयारी के पोट्रेयल को गलत साबित करने के लिए फिल्म अनाउंस कर दी है. पाकिस्तान की सिंध सरकार ने 'मेरी लयारी' नाम की एक फिल्म अनाउंस की है. इस फिल्म को दो पोस्टर भी सामने आए हैं. 13 दिसंबर को अनाउंस हुई इस फिल्म में लयारी के कल्चर को दिखाया जाएगा ताकि 'धुरंधर' में लयारी के कथित चित्रण को गलत साबित किया जा सके।

दिलजीत के बाद वरुण धवन ने भी छोड़ी 'नो एंट्री 2'

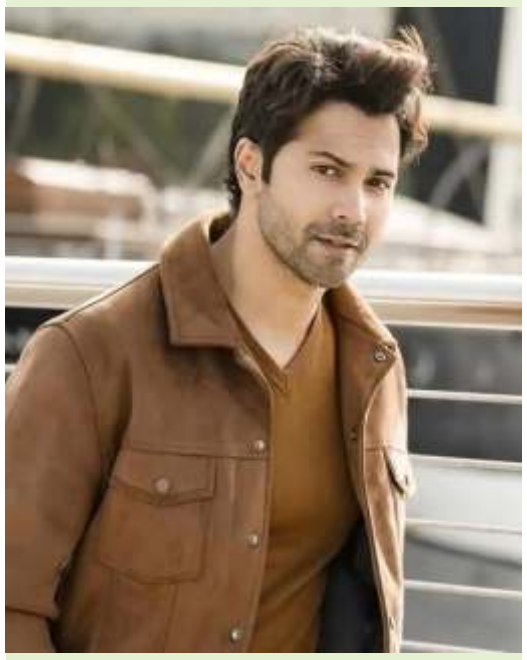

बॉलीवुड फिल्ममेकर बोनी कपूर एक बार फिर 'नो एंट्री' के जरिए बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है. फिल्म की घोषणा कुछ वक्त पहले ही की गई थी. फिल्म के सीक्वल को अर्जुन कपूर, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन के साथ बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों पहले दिलजीत से फिल्म से किनारा कर लिया. अब खबरें हैं कि वरुण फिल्म को बाय-बाय कह दिया है.

मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार वरुण धवन अब 'नो एंट्री' का हिस्सा नहीं है. दरअसल एक्टर इन दिनों अपने दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स में बिजी चल रहे हैं. इसलिए उन्हें 'नो एंट्री' की शूटिंग के लिए डेट्स की प्रॉब्लम हो रही है. फिल्म से जुड़े सूत्रों ने बताया वरुण इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटिड थे. लेकिन दिलजीत दोसांझ के फिल्म छोड़ने के बाद सारी चीजें बदल गई. अब वरुण भी 'भेड़िया 2' में बिजी चल रहे हैं. हालांकि इस दिक्कत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है. अभी मेकर्स ने भी इसपर कोई बयान नहीं दिया है.

सीक्वल्स के भरोसे अजय देवगन ने गुजारा 2025

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की हर साल कई फिल्में रिलीज होती हैं. 2025 में भी उनकी कई फिल्में पर्दे पर आईं और अब अगले साल भी उनकी कई फिल्में थिएटर्स में दस्तक देने के लिए तैयार हैं. एक्टर की इस साल कुल 3 फिल्में रिलीज हुईं और लेकिन खास बात ये है कि ये तीनों ही फिल्में सीक्वल थीं. इनमें से सिर्फ एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, बाकी दो फिल्में औंधे मुंह गिर गई.

अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' उनकी मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक थी. सैकनिल्क के मुताबिक 'रेड 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 173.05 करोड़ रुपए कमाए थे. इसी के साथ ये क्राइम-थ्रिलर फिल्म अजय देवगन की हिट फिल्मों में शामिल हो गई. 'सन ऑफ सरदार 2' साल 2012 में आई कॉमेडी फिल्म 'सन ऑफ सरदार' का सीक्वल है. लेकिन 'सैयारा' की आंधी में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो गई है. 'सन ऑफ सरदार 2' बॉक्स ऑफिस पर महज 46.82 करोड़ कमाकर फ्लॉप साबित हुई. अजय देवगन की रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' भी इसी साल रिलीज हुई थी. लेकिन 'सन ऑफ सरदार 2' की तरह 'दे दे प्यार दे 2' भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ नहीं बना पाई. 74.02 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ 'दे दे प्यार दे 2' भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई.

काजोल और फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर जताई खुशी

'कभी खुशी कभी गम' को पूरे हुए 24 साल काजोल बोलीं- 'राहुल कहीं न कहीं तो है'

90 के दशक में कई पारिवारिक और मल्टीस्टारर फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी रहीं, जो लोगों के जहन में एक बार बसीं तो फिर निकली ही नहीं. ऐसी ही एक फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' रही, जिसमें परिवार की गरिमा, अमीर-गरीब की सीमा पार करता प्यार और तीन पीढ़ियों का संगम दिखाया गया था. आज फिल्म ने अपने 24 साल पूरे कर लिए हैं एक्ट्रेस काजोल और फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर खुशी जताई है.काजोल ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा- 'सभी अंजलि को मेरा संदेश, खुलकर और गर्व से अपनी बात कहती रहो! राहुल कहीं न कहीं तो है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से शायद उसे देर हो गई है.' वहीं करण जौहर ने फिल्म के कुछ सीन शेयर कर लिखा- 'इतने सालों बाद भी यह सबको परिवार, प्यार, ढेर सारी खुशी और थोड़ा गम की ताकत का एहसास कराती रहती है'. इस फिल्म ने शाहरुख खान और काजोल को आइकॉनिक जोड़ी के रूप में पेश किया, जिसमें काजोल के चुलबुले अंदाज ने फैंस का सबसे ज्यादा दिल जीता था.

करण जौहर के दिल के करीब है फिल्म

करण जौहर के लिए भी ये फिल्म दिल के बहुत करीब है. उन्होंने निर्देशक और निर्माता सूरज बडजात्या को टक्कर देते हुए हिंदी सिनेमा को बड़ी और हिट पारिवारिक फिल्म दी थी. इससे पहले पारिवारिक और रोमांस से भरी फिल्मों के लिए सूरज बडजात्या को ही जाना जाता था. करण जौहर ने फिल्म की स्टारकास्ट को भी एक ही दिन में साइन किया था. निर्माता ने एक दिन में फिल्म के 6 बड़े स्टार्स को साइन किया.

एक ही दिन में साइन की थी स्टारकास्ट

करण जौहर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वे फिल्म में सभी बड़े स्टार्स को शामिल करना चाहते थे. उन्होंने कहा कि एक दिन वे स्क्रिप्ट लेकर पहले शाहरुख खान के घर पहुंचे, जहां उन्होंने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही फिल्म के लिए 'हां' कर दी थी. जिसके बाद काजोल ने 'हां' किया, फिर वो अमिताभ बच्चन और जया के घर पहुंचे और कहानी सुनाई और फिर दोनों ने फिल्म के लिए 'हां' कहा.आखिर में मैं ऋतिक रोशन और करीना कपूर के घर पहुंचा था.

छत्तीसगढ़ी रंगमंच का रोचक इतिहास

छत्तीसगढ़ में 1740 में मराठों का शासन काल आया। इनकी स्थापना का असर अंचल की कला और संस्कृति पर भी पड़ा। बीसवीं सदी के सातवें दशक से नेमीचंद जैन द्वारा संपादित नटरंग पत्रिका में हबीब तनवीर का नाचा पर केंद्रित कुछ लेख प्रकाशित हुआ। इसी दौरान अस्सी के दशक में राजिम में उनके द्वारा आयोजित नाट्य वर्कशॉप महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। छत्तीसगढ़ी रंगमंच पर इन घटनाओं का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। कतिपय विद्वान चनैनी नृत्याभिनय को छत्तीसगढ़ी रंगमंच की प्रारंभिक अवस्था मानते हैं। चनैनी लोरिक और चंदा की प्रेम गाथा है। भक्ति आंदोलन के प्रभाव के फलस्वरूप भारत में भगवान राम और कृष्ण की लीलाओं का मंचन प्रारंभ हुआ। इससे मिलती जुलती कथा को लेकर छत्तीसगढ़ी में भी एक लोकगीत मिलता है। यह गीत डा. श्यामाचरण दुबे की पुस्तक' फील्ड सांग्स आफ छत्तीसगढ़ ' में ' बोधरू गीत' के नाम से संकलित है। बोधरू गीत को परम्परा से जोड़ा जाए तो छत्तीसगढ़ रंगमंच की परम्परा मुगलकालीन प्रतीत होता है। भारत की आजादी के आसपास कृष्ण लीला मंडली की स्थापना का प्रभाव क्षेत्र सिर्फ बिलासपुर जिलाथा। वर्तमान उड़ीसा और महाराष्ट्र का एक बड़ा भू भाग क्रमशः 1905 और 1956 के पूर्व मिलकर छत्तीसगढ़ प्रांत कहलाता था। इस कारण उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु के भक्ति आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ा। भगवान कृष्ण की परिक्रमा करते कीर्तन की परम्परा प्रारंभ हुई। यह परम्परा आगे बढ़ कर रहस का रूप लिया। रहस की इस नाट्य परम्परा को राधा विहार और बृज विलास नामक कृतियां निरंतरता प्रदान करती हैं। इसी समय महाराष्ट्र का लोक मनोरंजन का साधन नाचा छत्तीसगढ़ में अपना रंग जमाने लगा। इसी काल खण्ड में दाऊ रामचंद्र देशमुख ने रंगमंच की दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस प्रकार एक लंबे समय से छत्तीसगढ़ी में नाट्य लेखन की परम्परा तो मिलती है, किन्तु मंच के अभाव में निरर्थकता का शिकार भी हो रही है।

देवार जाति की स्त्रियों द्वारा गाया जाता है बीरम गीत

शकुन्तला वर्मा

छत्तीसगढ़ अंचल में खानाबदोश देवार जाति की खियों द्वारा बीरम गीत गाई जाती है। घुमक्कड़ स्वभाव के कारण इन प्रचलित बीरम गीतों में विभिन्न क्षेत्रों के ऐतिहासिक संदर्भों का बखान मिलता है। बीरम गीत के बीच जब खियां चूड़ी खनकाती हैं, तब यह गीत उनके करुण एवं हृदय विदारक जीवन से मिलकर रस की वर्षा करता है। बीरम गीत में नारी जीवन की चिरंतर व्यथा का विशेष रूप से चित्रण हुआ है। नारी अपने मायके में सुखी जीवन जीती है पर ससुराल के नाम से वह व्यथित हो जाती है। देखें यह भाव इस गीत में -

मइके के खोल बड़ सोहन मोर ददा, रेंग लेहो बइहा झकोर।

ससुरे के खोल बड़ साकुर मोर ददा, रेंग लेहो बइहा सकेल।

इस गीत में माइके और ससुराल के मध्य अपने हृदय के अंदर पनप रहे भाव को पिता के समक्ष प्रकट कर रही है। एक अन्य पंक्ति जिसमें अपनी पीड़ा इस तरह व्यक्त करती हैं -

अंगना में कुआं खनाय लेते मोर ददा, धियरी ल देते धकेल। ऊपर पथना पिटाई देते मोर ददा ओ गंगा कर लेते असनान । आगे कहती है कि आप घर के आंगन में कुआं खुदवा कर उसमें मुझे धकेल देते और फिर गंगा स्नान कर लेते।

एक और भाव इस पंक्ति में -

उड़त चिरैया ल तै झन टिपिबे गा पीठ के बहिनी समान। अपन घर बेटवा अऊ पर घर बिटिया गा जोड़ी लिखीन भगवान।

यह गीत के माध्यम से कहना चाहती है कि चिड़िया को मत मारो बहन के समान होती है। बेटा घर का और बेटी पराए घर की होती है। यह जोड़ी तो भगवान की बनाई हुई है।

ददरिया में भावों से भरा काव्य बिम्ब

डा. जीवन यदु

छत्तीसगढ़ में कृषि कार्य के समय ददरिया श्रम परिहार का गीत ही नहीं है वह समझदार लोक का काव्य भी है, जिसमें सामाजिक जीवन के अनेक क्षेत्रों की अभिव्यक्तियां हैं, काव्य सम्मत प्रतीक और बिम्ब भी है। प्रतीक और बिम्ब मनुष्य की लम्बी यात्रा में संग्रहित अनुभवों के काव्य रूप होते हैं। यदि लोक गीतों में प्रतीक और बिम्ब आते हैं तो इसका अर्थ यही निकलता है कि लोक उतना नासमझ नहीं है, जितना कि उसे समझ लिया गया है। इसके उल्टे वह काव्य की समझ रखने वाला समाज है। काव्य में प्रतीकों में कुछ कह देना समझदारी वाला काम है। पुराने पड़ते प्रतीकों से बिम्बो का जन्म होता है। बिंबों से हमें ऐसे छाया लोक के दर्शन होते हैं जहां से काव्य में शब्द, पद, पंक्ति, समय और स्थान के अनुसार व्यंजना प्रधान संकेत प्रकट करने लगते हैं तब हम उसे एक ही सीमित अर्थ में बांध नहीं सकते हैं किन्तु वे वर्तमान में प्रवेश कर जाते हैं यही उसकी काव्य सफलता होती है। ददरिया लोक गीत में जो लोक मन उभरता है, वह अन्य लोकगीतों में उपस्थित लोक मन की तरह विस्तृत और विशाल है। इस लोक मन का कोई ओर है न छोर। धरती आकाश को एक साथ पा लेना इस लोक मन के लिए एकदम सहज है। लोक मन अपने भूगोल ज्ञान से शिक्षितों और भौगोलिक ज्ञान को चुनौती देता है। वह ग्रह नक्षत्रों को अपनी हथेली पर रखे पुलकित हो जाता है।

कल्चुरीकालीन शाक्त प्रतिमाएं

डॉ. पुष्पा तिवारी

दक्षिण कोसल क्षेत्र में शक्ति उपासना का परिचय अभिलेखों एवं अन्य कलाकृतियों से प्राप्त होता है। पार्वती, शैलदुहिता, दुर्गा, पर्वतसुता, गौरी, एकवीरा के मंदिर दक्षिण कोसल की विशेषता है। बिलासपुर के पुजारीपाल से प्राप्त गोपालदेव के शिलालेख में देवी के अनेक नामों में उनकी वंदना की गई है। यथा वाराही, भुजंगवल्या, त्रयि, जया, विजया, तारा, विंध्यवासिनी, महामाया, महाकाली, चंडिका, कामाक्षी जैसे अनेक नाम हमें मिलते हैं।

माता दुर्गा की प्रतिमाएं प्रमुख रूप से दो स्वरूपों में प्राप्त होती है। सप्तमातृकाओं की मूर्तियां दक्षिण कोसल के देवी मंदिरों की ही नहीं वरन सभी मंदिरों की विशेषता रही है। कहीं कहीं मातृकाएं की संख्या आठ और नौ भी पाई गई हैं। रायपुर संग्रहालय में डीपाडीह से उपलब्ध चतुर्भुजी पार्वती की प्रतिमा संरक्षित है जो बारहवीं सदी की मूर्ति कला पर प्रकाश डालती हैं। प्रतिमा के दोनों हाथों में आयुध स्पष्ट है तथा निचले दाएं हाथ में अक्षमाला एवं निचले बाएं हाथ में कमण्डल है। पार्वती के दोनों ओर परिचारिकाएं हैं। नंदी देवियों को भी शक्ति रूप में स्वीकार किया गया है। सौम्य रूप में गौरी की अनेक प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें प्रमुखता से गौरी को तप करते हुए चित्रित किया गया है। लाफा की पहाड़ी पर कल्चुरीकालीन महिषासुर मर्दिनी का मंदिर आज भी अपनी गौरव गाथा सुना रहा है। अतः नारी सौंदर्य के माध्यम से मूर्ति कला को पूर्णता प्रदान की गई है।

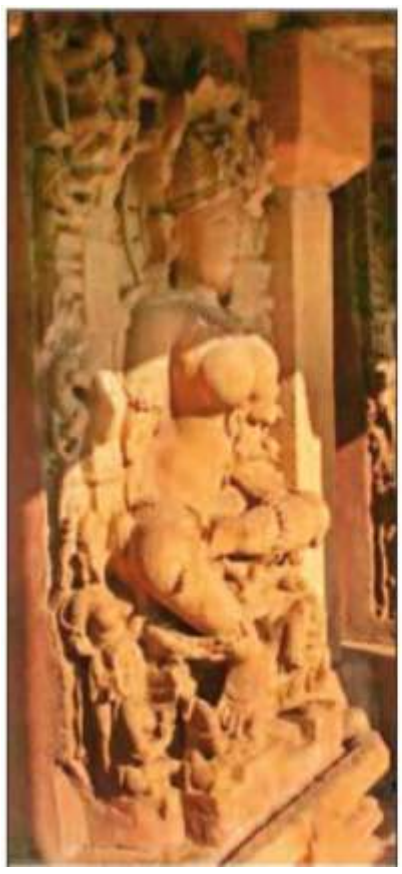

साप्ताहिक शहर सत्ता

लाल आतंक को फुटबॉल किक

31 मार्च तक नक्सलवाद होगा खत्म

- हर घर में सुविधाएं और हर गांव में समृद्धि का संकल्प
- बस्तर के 7 जिले देश में सर्वाधिक विकसित आदिवासी जिला बनेंगे

देश और राज्यों के लिए नासूर बन चुके लाल आतंक के खिलाफ छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने एक फुटबॉल किक मारने वाली है। खून की होली खेलने वाले नक्सलियों को गृहमंत्री अमित शाह बेसबॉल शॉट मर चुके हैं। हिदायत और समर्पण करने का एक मौका देकर केंद्र और राज्य सरकार ने इस समस्या को लगभग ख़त्म कर दिया है। नमाओवाद अगले साल 2026 में पूरे देश में नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। वहीं 2030 तक बस्तर के सभी 7 जिले देश में सर्वाधिक विकसित आदिवासी जिला बनेंगे। हर व्यक्ति के घर में बिजली, पानी, शौचालय, गैस सिलेंडर, 5 किलो अनाज और 5 लाख का मुफ्त इलाज तथा हर गांव में समृद्धि लाना भाजपा का संकल्प है. यह पूरा होगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को शहर के प्रियदर्शनी स्टेडियम में बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में यह उदगार व्यक्त किए।

शहर सत्ता/रायपुर। अपने 21 मिनट के भाषण में उन्होंने कई बार नक्सल समस्या के खात्मे का उल्लेख किया। साथ ही अभी जो भटके हुए युवा हैं, उन्हें अपने तथा परिवार के कल्याण के लिए शांति के मार्ग पर लौट आने की अपील भी की। उन्होंने समाज सुधारक और आदिवासी समेत अन्य समाज के लोगों से भी इसमें आगे आकर बचे हुए नक्सलियों के समर्पण में पहल करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगला ओलंपिक बस्तर के नक्सलमुक्त वातावरण में होगा और मैं फिर आऊंगा। नक्सलवाद से मुक्त होकर हमारे आदिवासी भाई खुशहाल जीवन जिएं यही हमारी मंशा है। शुरूआत में उन्होंने मां दंतेश्वरी के चरणों में नमन करते कहा कि मां से प्रार्थना है कि बस्तर की भूमि में फिर से खुशहाली लौटे। और सभी लोग खुशहाल जीवन जिएं।

उन्होंने आंगा देवा, बूढ़ा देव, गुंडाधुर और शहीद वीर नारायण सिंह को नमन करते कहा कि बस्तर और छत्तीसगढ़ की भूमि में संसाधनों की कमी नहीं है। लाल आतंक से मुक्त होने के बाद पूरा इलाका देश का सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और संकल्प है कि आदिवासी क्षेत्र के लोग भी समान रूप से आगे बढ़ें। नए उद्योग, उच्च शिक्षा, अस्पताल और वनोपज का प्रोसेसिंग प्लांट सभी जिले में स्थापित होगा। छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति अति सुंदर है। जिसमें हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटे नक्सलियों को हर तरह की सुविधा और संसाधन की व्यवस्था है।

साहस और संकल्प से आएगी समृद्धि

उप मुख्यमंत्री अरूण साव तथा विजय शर्मा ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के साहस और संकल्प से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश के पूर्वोतर और जम्मू कश्मीर जैसे अशांत क्षेत्र भी विकास के मार्ग पर चल पड़े हैं। बस्तर में उनके प्रयास से शांति और समृद्धि आएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तथा विधायक किरण देव ने कहा कि बस्तर करवट बदल रहा है। नक्सल आतंक ने बस्तर का सुख चैन छीन लिया था। जिसे दृढ़ इच्छा शक्ति से विकास की ओर ले जाने का काम केंद्र और राज्य सरकार कर रही है।

मांदर की थाप सुनाई देगी

विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने का साहसिक निर्णय और नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प अमित शाह को सदियों तक लोग याद रखेंगे। बस्तर के साल वन में बारूद सुरंग की जगह मांदर की थाप पर लोग थिरकेंगे।

नुवा बांट शांति का रास्ता

केंद्रीय गृहमंत्री ने जुवा बांट को शांति का रास्ता बताते इसपर चलकर विकास का रास्ता चुनने की अपील की। उन्होंने कहा भारत की संस्कृति पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। जनजातियों का खान पान, परिवेश, वाद्य, नृत्य और पारंपरिक खेल का समृद्ध विरासत मिला है। जिसे खेल आयोजन में खिलाड़ियों ने प्रतिभा दिखाकर साबित किया।

विकास में बड़ा बाधक रहा नक्सलवाद

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकास में सबसे बड़ा बाधक नक्सलवाद रहा है। गृहमंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण बस्तर शांति के पथ पर चल पड़ा है। यहां जवान साहस के साथ लड़ रहे हैं। 400 से ज्यादा सुरक्षा कैंप के स्थापित होने से सुदूर गांव तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही है। नक्सल समस्या खत्म होगी और बस्तर में फिर से शांति और खुशहाली आएगी।

दिन रात करेंगे परिश्रम

अमित शाह ने कहा कि बस्तर ओलंपिक खेल में समर्पित और पीड़ित परिवार को खेलते देख काफी आनंद आया। इसमें सुंदर भविष्य का सपना देखने वाले युवा भी शामिल है। इस तरह आने वाले समय में नक्सलवाद समाप्त होने के बाद आगे अंजाम तक पहुंचाने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से किसी का भला नहीं हुआ। हथियार उठाने वाले और यहां के आदिवासी दोनों को नुकसान उठाना पड़ा।

कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में दिखेंगी प्रतिभाएं

अमित शाह ने कहा कि इस ओलंपिक में 3 लाख 91 हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिनमें संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में 2600 पहुंचे। यहां एक टीम आई है जो यहां की खेल प्रतिभाओं को तराशेगी। कामनवेल्थ और ओलंपिक में यहां के खिलाड़ी पहुंच सके, इस पर टीम काम करेगी।

लाल सलाम की जगह भारत माता की जय के नारे

अमित शाह ने कहा कि यहां गोलियों की गूंज सुनाई देती थी। स्कूलों में घंटियों के जगह गोला, बारूद, बंदूक की आवाज आती थी। जहां सड़क बनाना सपना था वहां राजमार्ग बन रहे हैं। जहां लाल सलाम बोला जाता था वहां भारत माता की जय कहा जा रहा है। इस तरह का बदलाव बस्तर में आया है।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.), मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)। डाक पंजीयन - CG/RYP/DN/70/2025-27